● वर्ष-3
● अंक-01
रायपुर, बुधवार
09 अगस्त 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरु

पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर हुआ वार-पलटवार, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया

नईदिल्ली। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा की शुरुआत हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन तक चर्चा चलेगी। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा का जवाब देंगे। पहले दिन की चर्चा के बाद लोकसभा की कार्यवाही 6ः00 बजे शाम में स्थगित कर दी गई। बुधवार को एक बार फिर से 11ः00 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। मणिपुर मामले को लेकर विपक्षी दलों द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान विपक्षी द्वारा 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।

वहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी तंज कसा। मोदी ने कहा कि विपक्ष अविश्वास से भरा हुआ है और इसे दिखाने के लिए वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। वहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में भी जबरदस्त वार-पलटवार की राजनीति देखने को मिली। सत्ता पक्ष और एनडीए के सहयोगियों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के कार्यकाल का बखान किया तो वहीं विपक्षी दलों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। चलिए आपको बताते हैं कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर किसने क्या कहा।

लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और 'डबल इंजन' सरकार पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'मौनव्रत' तोड़ा जा सके। गोगोई ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखते हुए यह सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पद पर क्यों बनाए रखा? उन्होंने दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मौन रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी छवि से लगाव है और वह अपनी सरकार

की विफलताओं को सामने नहीं आने देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं जो गरीब परिवार से आते हैं और जिन्होंने गरीब जनता को मकान, शौचालय और पीने का पानी उपलब्ध कराया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, ''आज यह अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ लाया गया है। यह प्रस्ताव उस व्यक्ति (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) के खिलाफ है जिसने गरीबों को मकान बनाकर दिये, जिसने गरीब जनता को पीने का पानी दिया, शौचालय दिये, जिसने गरीब के घर में उजाला लाने की कोशिश की।'' दुबे ने कहा कि विपक्षी दलों का विरोध इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में गरीब के घर में चूल्हा क्यों जल रहा है, विदेशी नेता प्रधानमंत्री का सम्मान क्यों करते हैं।

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा में मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उस समय हनुमान चालीसा के कुछ अंश पढ़े, जब एक विपक्षी सदस्य ने यह सवाल कर दिया कि क्या उन्हें हनुमान चालीसा याद है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए शिंदे ने कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 'महा विकास आघाड़ी' और इस गठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी रोक थी। इस दौरान किसी विपक्षी सदस्य ने श्रीकांत शिंदे से कहा, ''क्या आपको हनुमान चालीसा याद है?'' शिंदे ने तत्काल हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म की बात की थी और आज द्रमुक उसके साथ खड़ी है जो राजधर्म निभाता दिख रहा है। द्रमुक के टीआर बालू ने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर उनके कुछ मित्र हैं, वाजपेयी जी की पार्टी होने के नाते सत्तारूढ़ पार्टी से उनका जुड़ाव रहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मित्र ही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार को बुराई ने घेर लिया है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

समाजवादी पार्टी (सपा) ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर मणिपुर के मुद्दे पर संवेदनहीनता दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार 'अहंकार' में डूबी है और उत्तर पूर्व राज्य में हिंसा की घटनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जिम्मेदार है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जब महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात होती है तो उत्तर प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए। यादव ने दावा किया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में हर तीन घंटे में एक महिला का यौन उत्पीड़न होता है।

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, महिलाओं पर अत्याचार हुए लेकिन केंद्र सरकार 70 दिन चुप रही।

इन दिनों

✍ अभिनय आकाश

पहले क्यों नहीं बोले राहुल गांधी?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी संसद पहुंचे जहां मानसून सत्र चल रहा है। परिसर में प्रवेश करते समय कई विपक्षी सांसदों ने उनका भव्य स्वागत किया। गांधी परिवार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना की। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद 12 बजे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भाषण होने वाला था। लेकिन सदन में राहुल की जगह गौरव गोगोई बोले। जिस पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसको लेकर निशाना साधते हुए पूछा कि सत्ता पक्ष उनके भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने तो तंज कसते हुए कह दिया कि लगता है वो लेट से सोकर उठे होंगे। जिसके बाद संसद में हंगामा मच गया। बहरहाल, सियासी बवालों से इतर बताते हैं कि आपको आखिर कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी ने संसद में भाषण नहीं दिया। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो सदन में नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। दरअसल, कांग्रेस चाहती है कि सदन में जब नरेंद्र मोदी मौजूद हों। उसी वक्त राहुल गांधी का भाषण हो। इसका संदेश साफ है कि कांग्रेस मोदी के मुकाबले राहुल को पेश करना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। कांग्रेस संसद में पहले से ज्यादा आक्रमक नजर आ रही है। संसद में राहुल गांधी ही पार्टी को लीड करते नजर आएंगे। कांग्रेस चाहती है कि सदन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हो तभी राहुल गांधी अपना भाषण दें। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के न बोलने की एक और बड़ी वजह है। दरअसल, अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी सदन में अंतिम दिन यानी 10 अगस्त को बोलेंगे। कांग्रेस नहीं चाहती है कि पीएम मोदी महफिल लूट ले जाए। वहीं आज अगर राहुल गांधी भाषण दे देते तो उनका भाषण पुराना हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस का प्लान है कि राहुल गांधी का भाषण पीएम मोदी के भाषण से ठीक पहले हो। जिससे राहुल का भाषण चर्चा में रहे और लोगों को याद भी रहे। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी के भाषण के साथ राहुल के भाषण की तुलना कर नए सियासी समीकरण बनाने की कोशिश करेगी। लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि राहुल जननेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कांग्रेस को बोलने का मौका मिला है तो वो देश में ये संदेश देना चाहती है कि वो नॉर्थ ईस्ट को कितनी तवज्जो देती है। राहुल गांधी बोलते तो शायद मणिपुर के मुद्दे पर उतना असर नहीं पड़ता। गौरव असम से सांसद हैं उनके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की है। यही बात गौरव की स्पीच से भी झलकी।

गुजरात से शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण

नईदिल्ली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय तक चलने वाला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने %नवंबर से पहले% गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक मार्च की संभावना जताई थी। हालाँकि, मार्ग और तारीखों के बारे में विवरण अभी तक अपुष्ट है। मंगलवार को खबर की पुष्टि करते हुए, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य के भीतर पार्टी के नेता एक समानांतर मार्च करेंगे। प्रमुख कांग्रेस नेता पश्चिमी राज्य के विभिन्न हिस्सों में मार्च का नेतृत्व करेंगे।

गुजरात से मेघालय होगी यात्रा

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा

चरण गुजरात से मेघालय तक शुरू होगा। इससे पहले सोमवार को, गुजरात कांग्रेस ने कहा कि उसने नए बहाल सांसद को महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से अपनी यात्रा शुरू करने का निमंत्रण दिया है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष अमित चावड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि दूसरे चरण की शुरुआत प्रदेश से होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई राज्य इकाइयों ने पदयात्रा के दूसरे चरण के लिए इसी तरह के या अन्य सुझाव दिये हैं।

पहला चरण सफल रहा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से 4,000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा शुरू की थी और जनवरी के अंत में श्रीनगर में समाप्त हुई थी। जिसका लाभ पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिला। राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार, यात्रा ने निस्संदेह पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा से मुकाबला करने और दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखने के लिए नई ऊर्जा दी है और इसलिए 2024 के लोकसभा चुनावों और उससे पहले राज्य चुनावों में लाभ उठाने की दृष्टि से, कांग्रेस नेता अब अपनी दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि पैदल मार्च का पहला चरण जो पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ और 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के बाद 130 दिनों से अधिक समय बाद कश्मीर में समाप्त हुआ, बेहद सफल रहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जहां गुजरात से शुरू हो रहा है, वहीं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी पदयात्रा के जरिए राज्य की निकम्मी सरकार से महाराष्ट्र को मुक्त कराने के बीड़े की शुरुआत करेगी। इसके लिए राज्य के सभी संभाग में पदयात्रा निकालने की जिम्मेदारी प्रमुख नेताओं को दी गई है।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान आज मंगलवार शाम दलपत सागर के सामने नव निर्मित 'सेहत बाजार' मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहेदव सहित रागी पुड़ी, रागी दोसा, रागी ब्राउनी, रागी इडली एवं कोदो खीर का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कैफे संचालक महिलाओं से चर्चा कर मिलेट्स से बने उत्पादों की सराहना की और उन्हें शुभकामना स्वरूप 5 हजार रूपए की राशि प्रदान की।

प्रमुख समाचार

भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र हैः कमलनाथ

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने मंगलवार को कहा कि चूंकि देश में 82ः लोग हिंदू हैं, इसलिए भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने स्वयंभू धर्मगुरु धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग का जिक्र करते हुए यह

बात कही और कहा कि इस मामले पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह डेटा द्वारा समर्थित एक स्थापित तथ्य है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 82 प्रतिशत हिंदू हैं। यहां कोई बहस नहीं है कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। कांग्रेस नेता का यह बयान राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता द्वारा छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत करने के बाद कमलनाथ के बेटे सांसद नकुल कमल नाथ पर निशाना साधने के एक दिन बाद आया है। आलोचना ने नवगठित विपक्षी गठबंधन के भीतर आंतरिक संघर्ष की अटकलें बढ़ा दीं। शिवानंद तिवारी ने छिंदवाड़ा में धीरेंद्र शास्त्री की मेजबानी के लिए कांग्रेस सांसद नकुल कमल नाथ की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम प्रमुख ने खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की।

ज्ञानवापी सर्वे का छठा दिन, गुंबद पर पहुंची टीम

नईदिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक टीम ने मंगलवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण फिर से शुरू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या संरचना एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

एएसआई सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से यह छठा दिन है, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। विजुअल्स में एएसआई टीम को सुबह करीब 8 बजे से ज्ञानवापी मस्जिद के विभिन्न हिस्सों का सर्वेक्षण करते हुए दिखाया गया है। एएसआई के एक अधिकारी को मापने वाले टेप के साथ संरचना के गुंबद की एक खिड़की को मापते देखा गया। इससे पहले, एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर की दीवारों और स्तंभों पर उकेरे गए त्रिशूल, स्वस्तिक, घंटी और फूल जैसे प्रतीक की तस्वीरें और वीडियो लिए थे। एएसआई अधिकारियों ने प्रतीकों की निर्माण शैली को भी दर्ज किया। 4 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

एनडीए के 28 सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नईदिल्ली। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के 28 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री

राजनाथ सिंह और अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी 31 जुलाई से 10 अगस्त के बीच राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर यह काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले सोमवार, 7 अगस्त को प्रधानमंत्री ने आठ पूर्वोत्तर राज्यों - असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की थी। अब तक पीएम मोदी अलग-अलग राज्यों के एनडीए सांसदों के साथ छह क्लस्टर बैठकें कर चुके हैं। इस तरह की पांचवीं बैठक बिहार के सांसदों के साथ हुई, जिसे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में देखा जा रहा है।

केरल में समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पास

नईदिल्ली। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के केंद्र के कदम पर चिंता और निराशा व्यक्त करते हुए, केरल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। केंद्र के कदम को

जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बताते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दावा किया कि यूसीसी का कार्यान्वयन संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि संघ परिवार के लिए संविधान मनुस्मृति है। वे हमारे संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि संघ परिवार इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि यूसीसी की आवश्यकता है या नहीं। संविधान में कही गई यूसीसी की बात संघ परिवार के दिमाग में नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का भी आरोप लगाया। विजयन ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 44 केवल यह प्रस्तावित करता है कि राष्ट्र एक समान नागरिक संहिता को साकार करने का प्रयास करेगा।

बिष्णुपुर में चौकी से असम राइफल्स के जवानों को हटाया

इंफाल। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मोइरांग लमखाई चौकी पर तैनात असम राइफल्स के जवानों को हटा लिया गया है और उनकी जगह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) तथा राज्य पुलिस को तैनात कर दिया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। असम राइफल्स के जवानों को ऐसे समय में वापस बुलाया गया है जब घाटी के जिलों में महिलाओं के कई समूहों ने हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य से अर्धसैनिक बल को हटाने की मांग करते हुए सोमवार को प्रदर्शन किया था। बिष्णुपुर में पिछले सप्ताह फिर से हिंसा हुई थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) एल कैलुन द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, ''बिष्णुपुर के कांगवई रोड पर मोइरांग लमखाई चौकी पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक असम राइफाल्स के स्थान पर राज्य पुलिस और सीआरपीएफ की 128 बटालियन को तैनात किया जाएगा।'' असम राइफल्स से संपर्क किया गया है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। महिला समूहों ने सोमवार को इंफाल वेस्ट जिले के होदाम लीराक तथा क्राकीथेल और इंफाल ईस्ट के अंगोम लीकाई तथा खुरई इलाकों में एक सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। इस बीच इंफाल ईस्ट और वेस्ट जिलों के प्रशासन ने मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दो घंटे बढ़ा दी।

संसद का मानसून सत्र

राज्यसभा में हंगामा लेकिन कई विधेयकों को पास किया गया

नईदिल्ली। संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी चरण में है। आज संसद के दोनों सदनों में कुछ हद तक कामकाज हुए हैं। राज्यसभा में हालांकि अलग-अलग समय पर हंगामा देखने को मिला। इसके बावजूद कई विधेयकों को पास किया गया। दूसरी ओर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। दोनों सदन बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गए।

भाजपा बनाम कांग्रेस

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों से सरोकार नहीं है और वे एक ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं जो गरीब परिवार से आते हैं और जिन्होंने गरीब जनता को मकान, शौचालय और पीने का पानी उपलब्ध कराया है तथा उनके कल्याण की चिंता की है। लोकसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, महिलाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की समस्याओं से निपटने में 'डबल इंजन' सरकार पूरी तरह विफल रही है और यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'मौनव्रत' तोड़ने के लिए लाया गया है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा में मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उस समय हनुमान चालीसा के कुछ अंश पढ़े, जब एक विपक्षी सदस्य ने यह सवाल कर दिया कि क्या उन्हें हनुमान चालीसा याद है।

राज्यसभा की कार्यवाही

राज्यसभा में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेसके नेता डेरेक ओ'ब्रायन को उनके 'अशोभनीय आचरण' के कारण मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का

प्रस्ताव किया गया लेकिन बाद में सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे को निस्तारित करते हुए कहा कि सदस्य आगे से अपने आचरण को सदन की गरिमा के अनुरूप बनाएंगे।

राज्यसभा ने मंगलवार को राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक 2023 और 'राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023' को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक का उद्देश्य जहां देश में दंत चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करना तथा गुणवत्तापूर्ण और किफायती दंत चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना है वहीं राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक में परिचर्या और प्रसूति विद्या पेशेवरों (नर्सिंग एवं मिडवाइफ) संबंधी शिक्षा एवं सेवा मानकों के विनियमन, संस्थाओं के मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय रजिस्टर के रख-रखाव का उपबंध किया गया है। (मनसुख मांडविया)

भारत सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत संदिग्ध लेनदेन और संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राज्यसभा को मंगलवार को यह जानकारी दी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मीडिया पोर्टल न्यूजक्लिक के खिलाफ 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई की विपक्षी दलों द्वारा की गई आलोचना का हवाला देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि हो सकता है कि उन्होंने भारत की सुरक्षा और एकता को निशाना बनाने के लिए चीन के इशारे पर एक नया गठबंधन बनाया हो। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी द्वारा राज्यसभा में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) पर निशाना साधते हुए दावा किया कि न्यूज़क्लिक को चीनी फंडिंग संबंधी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने उनकी पोल खोल दी है। विपक्षी गठबंधन (इंडिया) के घटक दलों ने राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की एक टिप्पणी पर उनसे माफी की मांग करते हुए मंगलवार को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया।

संसद ने मंगलवार को 'भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक, 2023' को मंजूरी दी जिसमें मुंबई स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (नीति) को भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) का दर्जा दिया जा रहा है। राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों की गैर-मौजूदगी में संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। (धर्मेन्द्र प्रधान)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार कोआश्वासन दिया कि यदि देश की सुरक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पांच से छह प्रतिशत भी खर्च करना पड़ा तो सरकार इससे पीछे नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सेनाएं हर प्रकार की युद्धकला के लिए तैयार हैं। अंतर सेना संगठन (कमान, नियंत्रण एवं अनुशासन) विधेयक 2023 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। उनके जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

कैम्पा मद में अधिकारी व कर्मचारी डकार गए जानवरों के चारागाह की राशि

■ आरटीआई से हुआ खुलासा

बीजापुर। हाल के दिनों में बाघ के शिकार और तस्करी को लेकर सुर्खियों में रहे बीजापुर स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के पामेड़ अभ्यारण्य में चारागाह विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े को विभाग के ही जिम्मेदार कुछ अफसर-कर्मियों ने मिलकर अंजाम दिया और कैम्पा मद की एक बड़ी राशि डकार ली। विभाग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त जानकारी ने ही पूरे मामले की पोल खोल कर रखी दी है। भ्रष्टाचार की मंशा को मुकम्मल करने जिम्मेदारों ने फर्जी मस्टररोल तैयार कर करीब 3 लाख 31 हजार 284 रुपये का आहरण कर लिया। जबकि मस्टररोल में जिन मजदूरों के नाम दर्ज हैं, जांच में वे सभी फर्जी पाए गए।

मामले की तह तक जाने सबसे पहले विभाग में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए विभाग की तरफ से कार्य से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए थे। इसमें पामेड़ अभ्यारण्य अंतर्गत धरमाराम परिक्षेत्र के भट्टीगुड़ा के कक्ष क्रमांक 848, सहायक परिक्षेत्र कंवरगट्टा और कंचाल कक्ष क्रमांक865 में वर्ष 2020 में कार्य होना बताया गया।

इस कार्य के लिए 3 लाख 31 हजार 769 रुपये की

राशि कैम्पा मद से वर्ष 2019 में स्वीकृत की गई थी। इसके तहत कई हेक्टेयर भूभाग पर बीज बोआई, पाटा चलाई, सीबीओ, क्षेत्र सफाई, लेन्टाना, यूपेटोरियम, वनतुलसा व अन्य बीड़ उन्मूलन, अखाद्यय घास, कड़ी मिट्टी में चेकडेम निर्माण आदि कार्य शामिल थे।

प्रतिदिन 295 रुपये प्रति मजदूर भुगतान की दर से काम कराया जाना था, लेकिन रेंज के ही जिम्मेदार अफसर व कर्मचारियों ने चारागाह विकास के तहत जितने कार्य होने थे, उन्हें कराए बिना फर्जी बाउचर और इंक्लोजर लेटर (मस्टररोल) तैयार कर राशि आहरित कर ली। कैम्पा मद से स्वीकृत इस काम को एक महीने में पूरा करना बताया गया, जबकि स्थानीय ग्रामीण वर्ष 2020 में संबंधित कक्ष क्रमांक में कोई काम ना होने की बात कह रहे हैं।

बाउचर में परिसर रक्षक, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी धरमाराम और अधीक्षक पामेड़ अभ्यारण्य द्वारा हस्ताक्षर कर भौतिक सत्यापन दर्शाया गया है। वहीं, मिल रही शिकायतों की जांच की गई तो ग्रामीणों के कथन और मौका स्थल के निरीक्षण में कोई काम न होने की बात सामने आई है। कोंडापल्ली सरपंच मनीष यासम का आरोप है कि अधीक्षक, रेंजर और डिप्टी रेंजर ने मिलीभगत कर राशि आहरित कर ली और उन्हें भनक तक नहीं लगी। सूची में जिन मजदूरों के नाम दर्शाए गए हैं, उनका भी वास्ता इस काम से नहीं था। जब ग्रामीण और मजदूर ही काम होने से साफ इंकार कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर है कि पामेड़ अभ्यारण्य अंतर्गत वर्ष 2020 में चारागाह विकास के नाम पर अफसर व कर्मियों ने विभाग को अंधेरे में रखकर कैम्पा मद की बंदरबाट कर ली थी।

मामला उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिली है कि भ्रष्टाचार के सूत्रधार अधीक्षक को विभाग द्वारा दूसरे रेंज में स्थांनातरित कर दिया गया है। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर विभाग की चुप्पी के खिलाफ अब पंचायत ने ही मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। देखना होगा कि इस पर विभाग की नींद कब टूटेगी और भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अधीक्षक, परिक्षेत्र अधिकारी, परिसर रक्षक पर कार्रवाई आखिर कब तक होगी।

क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से सेवा करने का सौभाग्य मिला : रंजना साहू

धमतरी। ग्राम पंचायत देवरी जो विधानसभा के विधायक के लिए स्वर्णिम इतिहास जहां पर विधायक रंजना साहू ने 2018 में चुनाव जीतने के उपरांत विधानसभा विकास निधि के अंतर्गत सबसे पहला काम देवरी पंचायत को दिया गया था, उक्त बातें जिला साहू संघ अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य अवनेंद्र साहू ने ग्राम देवरी में लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम के दरमियान कहीं। ग्राम देवरी में विधायक निधि से स्वीकृत ढीमर समाज समुदायिक भवन के मरम्मत कार्य का भूमिपूजन , सरस्वती शिशु मंदिर के लिए भवन निर्माण का भूमि पूजन, साहू समाज भवन में शेड निर्माण का लोकार्पण विधायक रंजना डीपेंद्र साहू के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन ग्राम पंचायत के सरपंच रामनारायण ध्रुव ने समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए गांव के प्रमुख मांगों को विधायक को अवगत कराया।

विधायक श्रीमती साहू ने कहा कि क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से सेवा करने का सौभाग्य मिला, और निरंतर क्षेत्र में जनहित के कार्य किए जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जनता की मांगों को स्वीकार कर अति शीघ्र उसे पूरा करें, और इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहकर कार्य कर रहे हैं। भोथली मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बताया कि विधानसभा में निरंतर मुलभुत सुविधाओं को पूरा करने विधायक का प्रयास सराहनीय है,

उनके द्वारा क्षेत्र के जनहित मुद्दों को विधानसभा पटल पर रखी और परस्पर क्षेत्र में निरंतर जनहित के कार्य करा रही है। लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम के दरमियान जनता के मध्य विधायक रंजन साहू ने जाकर ग्रामीणों से चर्चा की और विभिन्न विषयों से ग्रामीणों से अवगत होकर निराकरण करने की बात कही। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य दमयंती साहू, तहसील साहू समाज अध्यक्ष गोपाल साहू, मंडल महामंत्री मिश्री पटेल, उपसरपंच शोभाराम सिन्हा, रमेश साहू, जीवन लाल साहू, दयालु राम चोवा राम साहू, टीका राम साहू, घुरऊ राम ढीमर, अर्जुन सिंह ओझा, रामेश्वर साहू भानु प्रताप, रोशन, टिंकू राम, रोहित, धनेश, छन्नूलाल, भंवरलाल, भीखम, धर्मराज, शकुन, योगेश्वरी, दीपा साहू, गायत्री, मंजू, स्नेहा, ईश्वरी, यमुना, रेखा ध्रुव, आरजी साहू, दूजराम सिन्हा, विष्णु राम साहू, परस लाल साहू, उषा चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

राजीव भवन धमतरी में एनएसयूआई की जिला कार्यकारणी बैठक हुई

धमतरी। रविवार को एनएसयूआई की जिला कार्यकारिणी की बैठक राजीव भवन धमतरी में संपन्न हुई। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन द्वारा यह बैठक आहूत की गई थी जिसमें संगठन के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगामी गतिविधियों को लेकर योजनाएं बनाई गई व सभी पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई।

एनएसयूआई की इस बैठक में आगामी कई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे स्वतंत्रता दिवस, स्कूल स्पोर्ट इवेंट व प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर एनएसयूआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले आयोजनों को लेकर योजनाएं बनाई गई। बैठक के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओ की उपस्थिति में एनएसयूआई के प्रदेश स्तरीय कैंपेन बात हे स्वाभिमान के हमर पहिली मतदान के का पोस्टर विमोचन राजीव भवन में किया गया। दिव्ययांग जन सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष मोहन लालवानी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना , महापौर विजय देवांगन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चंद्राकर के हाथों से इस कैंपेन का पोस्टर विमोचन संपन्न हुआ।

एनएसयूआई ने अपने नेता श्री राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने की खुशी में एनएसयूआई कार्यकताओं ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कचहरी चौक में राहगीरों को मिठाई बांटी।

एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने बताया कि आज एनएसयूआई कि जिला कार्यकारणी बैठक आयोजित कि गई जिसमें जिले भर से एनएसयूआई के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओ ने शिरकत कि और अपने क्षेत्रों में किए गए तमाम छात्र हितैषी कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, संगठन द्वारा कि गई गतिविधियों की समीक्षा इस बैठक के माध्यम से कि गई और आगामी गतिविधियों के लिए रणनीति निर्धारित की गई तत्पश्यात वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा जिले के युवा छात्र नेताओ के साथ प्रदेश एनएसयूआई के कैंपेन बात हे स्वाभिमान के हमर पहिली मतदान का पोस्टर विमोचन किया गया और नए और युवा वोटरों को भूपेश बघेल सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह करने को कहा गया। इसके उपरांत हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी की मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा में रोक लगाए जाने की खुशी में एनएसयूआई द्वारा शहर के वक्ष स्थल कचहरी चौक में मिठाई वितरित कर जश्न मनाया गया, राहुल जी की सजा पर रोक एक ओर से जहां सत्य की जीत है वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की बुनियाद की मजबूती भी है।

अपने अधिकारों के लिए मुखर हो: मरकाम

नगरी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। समस्त प्रदेश एवं सिहावा विधानसभा क्षेत्रवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व भर के मूल निवासियों को समर्पित यह दिवस अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता और उसके पालन को सुनिश्चित करने का दिवस है परंतु छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल प्रदेश में आदिवासी समाज पर लगातार हो रहे अत्याचार, भेदभाव, छात्रावास आश्रम की बालिकाओं का शोषण और दुराचार जैसी घटनाओं पर अपनी कान मूंदकर बैठी भूपेश बघेल की सरकार से निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर त्वरित कार्यवाही हेतु मांग पत्र लिखकर भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि 1. सुकमा के छात्रावास में 6 साल की आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले ने पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया है। इसपर कड़ी कार्रवाई की मांग करें साथ ही विगत वर्षों में आदिवासी छात्रावासों और कन्या आश्रमों में बालिकाओं के साथ यौन अपराध बढ़ गए हैं वे असुरक्षित हो गई है। पिछले वर्ष नारायणपुर के ओरछा से 4 बच्चियां लापता हो गई जिन्हे तमिलनाडु से बरामद किया गया। बीजापुर हॉस्टल में आदिवासी छात्रा से मारपीट जैसी कई खबरे मन को व्यथित कर देती है। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो कोई भी माता पिता अपनी बेटी को छात्रावास - आश्रम में रखकर पढ़ाने की सोचना बंद कर देंगे। 2. छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 से बस्तर सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग के पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्थानीय भर्ती प्रावधान को समाप्त कर दिया है जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यदि यह बहाल नहीं किया जाता तो स्थानीय आदिवासी बच्चे रोजगार से वंचित हो जायेंगे और वन की ओर विमुख हो जायेंगे। 3. प्रदेश में जनजाति समाज के जनसंख्या के अनुपात में 32ल आरक्षण प्रदान किया जाए विदित हो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 20ल आदिवासी आरक्षण रोस्टर के साथ भर्तियां कर रही है। इससे जनजातीय समाज के बेटे बेटियों को शिक्षा सत्र 2022 में 110 सीटों का नुकसान हुआ और 2023 में 160 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। अर्थात इतने आदिवासी बच्चे चिकित्सक बनने से वंचित हो जायेंगे। 4. जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी समाज को निर्णायक अधिकार देने के लिए पेसा कानून लाया गया था लेकिन भूपेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में बेहद ही कमजोर पेसा कानून का अनुपालन किया जा रहा है। ग्राम सभा की स्वीकृति किसी भी योजना, परियोजना या कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। हसदेव अरण्य में हजारों पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग ने इसी कमजोर प्रावधान का सहारा लिया। 5. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे शासकीय नौकरी करने वालों पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत खराब, छतों से टपका रहा पानी

कोरबा। कोरबा में महिला व बाल विकास विभाग के दफ्तरों की स्थिती बद से बदतर हो गई है। मरम्मत के अभाव में भवन जर्जर हो गए हैं, जिसके कारण बच्चों और गर्भवति महिलाओं को पोषण देने वाले विभाग के कार्यालय कुपोषण की मार झेल रहे हैं। जिला मुख्यालय के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के भवनों की भी स्थिती काफी खराब हो चुकी है। कई बार पत्राचार करने के बाद विभागीय कर्मियों की सुनने वाला कोई नहीं है।

महिला व बाल विकास विभाग से संबंधित कार्यालय और भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। मरम्मत के अभाव में भवन जर्जर होकर खंडहर का रुप लेते जा रहे रहे हैं। बावजूद इसके मरम्मत को लेकर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा करतला के परियोजना कार्यालय को देखकर असानी से लगाया जा रहा सकता है, जहां बारिश का पानी छत से टपक रहा है और उससे बचने के लिए कर्मचारी तिरपाल का सहारा ले रहे हैं।

कुछ दिन पहले ही जिला मुख्यालय में मौजूद मुख्य कार्यालय की तस्वीर सामने आई थी, जहां सिपेज के कारण छत्तीसगढ़ महतारी और मुख्यमंत्री की तस्वीरें खराब होने लगी थी। भवनों की ऐसी दशा पूरे जिले में है। विभागीय कार्यालयों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की भी यही स्थित है। अकेले करतला ब्लॉक के 35 केंद्र पूर्ण रुप से जर्जर हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत या फिर नए भवन की मांग परियोजना कार्यालय द्वारा पिछले लंबे समय से की जा रही है। लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा और नौनीहाल खतरे के साए में अक्षर ज्ञान ले रहे हैं। स्थिती अगर ऐसी ही रही तो वो दिन दूर नहीं जब कोई बड़ा हादसा हो जाए और लोगों की जान आफत में फंस जाए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ग्राम तरहुल से 84 नग सागौन चिरान जब्त

कांकेर। वन परिक्षेत्र दुर्गुकोंदल अंर्तगत ग्राम तरहुल में वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्रामीण तुकाराम गांवर पिता श्रीराम गांवर के घर में अवैध इमारती लकड़ी का भंडारण किया गया है। सूचना पर मंगलवार को वन विभाग की टीम ने ग्रामीण के घर दबिश देकर उसके पास से 84 नग सागौन चिरान जब्त किए हैं। जब्त लकड़ी की कीमत 68 हजार रुपए आंकी गई है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गकोन्दल वन परिक्षेत्र के ग्राम तरहूल में ग्रामीण तुकाराम गांवर के मकान बाड़ी में अवैध सागौन चिरान जमा कर रखे जाने की गुप्त सूचना के आधार पर वनमण्डलाधिकारी श्रीकृष्ण जाधव के निर्देशन में उप वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर आईपी. ग्रेन्द्रे, वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन भानुप्रतापपुर विजय पटनायक वन क्षेत्रपाल के नेतृत्व में दल गठित कर सर्च वारंट जारी किया गया तथा ग्रामीण तुकाराम गांवर निवासी ग्राम तरहूल के मकान बाड़ी की तलाशी ग्रामीणों के सहयोग से किया गया। तलाशी के दौरान मकान के भीतर कमरे में 84 नग सागौन चिरान फारा 0.984 घनमीटर छुपा कर रखा जाना पाया गया।

मलेरिया से दर्जन से अधिक लोग चपेट में आये, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

कोरबा। बरसात के दिनों में जल जमा होने से मच्छरों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में हो रही है और इससे जन स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। पाली विकासखंड के सोनईपुर में मलेरिया के 12 मरीजों को मिलने के बाद स्वास्थ विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ मरीजों को भर्ती किया गया। इनमें से सात मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरबा जिले के पाली विकासखंड के अंतर्गत पोंटापानी पंचायत के सोनइपुर गांव में जलजमाव के कारण 12 लोग मलेरिया की जद में आ गए। जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने यहां कैंप लगाने के साथ स्वास्थ्य परीक्षण किया। जबकि विधायक के द्वारा पीड़ितों के साथ-साथ ग्रामीणों को मेडिकेटेड मच्छरदानी बांटी गई। कोरबा के सीएमएचओ डॉक्टर एसएन केसरी ने बताया कि सोनपुर में 12 लोगों को मलेरिया से पीड़ित पाया गया था। इनमें से सात लोग डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और वर्तमान में पांच लोगों का उपचार किया जा रहा है।

प्रदेश स्तरीय माखन हांडी लूट प्रतियोगिता की तैयारी शुरु

दुर्ग। छत्तीसगढ़ कोसरिया अहीर यादव समाज द्वारा 10 सितम्बर को आजाद चौक बस स्टैण्ड गौठान मंच पाटन में आयोजित प्रदेश स्तरीय माखन हांडी लूट प्रतियोगिता की तैयारी अभी से शुरु हो गई है। जिसके पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने किया। यादव समाज के गहिरा गुरु राजेश यादव ने बताया कि मक्खन हांडी लूट प्रतियोगिता का प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से अनेक मक्खन हांडी लूट प्रतियोगियों का समूह शामिल होंगे। जिसके लिए निशुल्क भोजन, आवास व ठहरने की व्यवस्था किए गए है। पुरुष वर्ग प्रथम पुरस्कार 21,000 रूपए(25 फीट हाईट) महिला वर्ग प्रथम पुरस्कार 11,000 रूपये (15फीट हाईट) बाल गोपाल प्रथम पुरस्कार 5000रूपये, (10 फीट हाईट) रहेगा। अन्य प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ कोसरिया अहीर यादव सेवा समाज पाटन, जिला दुर्ग द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा।

बीमा की रकम दिलाने का झांसा देकर हाईकोर्ट कर्मी से चार लाख की धोखाधड़ी

बिलासपुर। हाईकोर्ट के कर्मचारी को बीमा की रकम वापस दिलाने का झांसा देकर चार लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत चकरभाठा थाने में की है। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। हाई कोर्ट आवासीय परिसर में रहने वाले अमित कुमार ताम्रकार ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उन्होंने निजी बीमा कंपनी में इंश्योरेंस कराया है। इसकी बोनस राशि दिलाने के नाम पर उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से काल आया। फोन करने वालों ने अपने आप को बीमा लोकपाल कार्यालय है दराबाद और बीमा लोकपाल कार्यालय मुंबई का अधिकारी बताया। उन्होंने अगस्त 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक अलग-अलग किश्तों में चार लाख नौ हजार 225 रुपये ले लिए। इसके बाद भी उन्हें बीमा की रकम और बोनस नहीं मिला। उनके खाते में रुपये नहीं आने पर धोखाधड़ी की आशंका हुई। बाद में जालसाजों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए।

बीएमएस समान काम समान वेतन को लेकर करेगा आंदोलन

कोरबा। विद्युत सुधार अधिनियम 2003 व विद्युत सुधार अधिनियम 2022 से बेरोजगारी के साथ ही उत्पादन व वितरण कंपनी में ठेका मजदूरों की संख्या बढ़ी है। ठेका मजदूरों को समान काम का सामान वेतन दिलाने, केंद्र सरकार से विद्युत की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग को लेकर सितंबर से अक्टूबर तक आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। भारतीय मज़दूर संघ से संबंध अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का दो दिवसीय विस्तारित कार्यसमिति की बैठक केरल के एर्नाकुलम के भामसं कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान वर्तमान विद्युत व्यवस्था से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा की गई। इसमें सभी प्रदेशों में इलेक्ट्रिसिटी कि वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था को लेकर विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बिजली की वर्तमान व्यवस्था कर्मचारियों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा चरमरा गई है। इसके कारण छत्तीसगढ़ की तीनों कंपनियां अपने आप ही निजीकरण में चली गई है।

पीएम आवास की किस्त नहीं मिली तो लाभार्थी ने दी जान, भाजपा ने किया प्रदर्शन

राजनांदगांव। पीएम आवास के लाभार्थी की आत्महत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राजनांदगांव नगर निगम का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में नगर निगम पहुंचे और तीन बैरिकेड को तोड़कर नगर निगम परिसर में घुस गए। इस दौरान उन्होंने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी की मांग लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया।

दरअसल, 19 जुलाई को पीएम आवास की राशि मिलने में देरी होने के कारण कौरीनभाठा निवासी महादेव यादव ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पेंड्री में भर्ती

किया गया था। महादेव यादव की हालत बिगड़ने पर उसे रायपुर के अस्पताल भी रेफर किया गया था, लेकिन डॉक्टर की तमाम कोशिशें के बाद उसकी जान नहीं बच पाई और 5 अगस्त को महादेव यादव ने दम तोड़ दिया।

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और नगर निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिस के तमाम बंदोबस्त के बावजूद भाजपा के कार्यकर्ता बेरीकेटिंग को तोड़ते हुए नगर निगम कार्यालय परिसर में घुस गए और जमकर नारेबाजी की।

इसके बाद नगर निगम के अफसर मौके पर पहुंचे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा और पीड़ित महादेव यादव के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि महादेव यादव पीएम आवास योजना का लाभार्थी था।प्रधानमंत्री आवास की किस्त रेगुलर नहीं मिलने के कारण उसने जहर खा लिया था, जिसका लगातार अस्पताल में इलाज जारी था। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। नगर निगम की घोर लापरवाही के कारण यह घटना हुई है।

वहीं, नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर निगम तेजी से कार्य कर रहा है और बीते दिनों 8 करोड़ रुपये मिला था, जिसे एक माह के भीतर आवंटित कर दिया गया। यहां जैसे ही राशि प्राप्त होती है हितग्राहियों को आवंटित कर दी जाती है। वहीं, महादेव यादव की मौत के मामले में उन्होंने कहा कि इसमें जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस नेता पर मारपीट का लगा आरोप

कांकेर। महिला के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में कांग्रेस के लोकसभा आईटी सेल के अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 6 और लोगों को भी मामले में आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया है। भानुप्रतापपुर थाने में सम्बलपुर की रहने वाली श्रृंखला पंडा ने शिकायत की है।

महिला ने आरोप लगाया कि सोमवार दोपहर को गाड़ियों में सवार होकर अचानक कुछ लोग उसके घर पहुंचे और परिवार के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट करने वाले आरोपियों में कांग्रेस लोकसभा आईटी सेल का अध्यक्ष नमन जैन भी है।

संबलपुर निवासी पंडा परिवार और भानुप्रतापपुर निवासी जैन परिवार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। पंडा परिवार के नीलेश पंडा ने परिवार को बिना बताए संबलपुर का अपना मकान भानुप्रतापपुर के नीलेश जैन को बेचने का सौदा करते हुए 15 लाख रुपए लिए थे। सौदे के कुछ समय बाद नीलेश पंडा ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद जैन परिवार के लोगों ने मकान को लेकर हुए सौदे की जानकारी दी और दस्तावेज पेश किए। मृतक नीलेश पंडा के बड़े भाई दिनेश पंडा ने सौदे की जानकारी होने से इंकार किया, लेकिन दस्तावेज देखने के बाद कहा कि वह 15 लाख लौटा देगा। इस बीच पंडा परिवार पैसे नहीं लौटा पाया तो जैन परिवार दबाव बनाने लगा। पीड़ित परिवार ने जैन परिवार पर अपने साथियों के साथ मकान खाली करने का दबाव बनाने के साथ ही मारपीट का आरोप लगाया है। इस मारपीट में महिला, उसके सास ससुर को चोटें आई। महिला और दिनेश पंडा पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत की। एसआई संदीप बंजारे ने बताया कि पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ केस फाइल की। नीलेश जैन, नमन जैन, दीपक जैन, जीवन जैन, संजू नेताम और ज्ञानेश्वर बघेल के खिलाफ पुलिस ने धारा 451, 147, 294, 323, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। दूसरे पक्ष का भी आवेदन आया था जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

विपक्षी गठबंधन विश्वास की कमी से आपस में जूझ रहा

नईदिल्ली। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन्होंने वंशवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्ट राजनीति के जरिये इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन आपस में विश्वास की कमी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करता है और इसीलिए तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को बहुत घमंड हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घमंडिया ताकत को एकता से जवाब दें। मोदी ने बैठक में नारा देते हुए कहा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद भारत छोड़ो। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिये एक सुनहरा अवसर है।

राहुल गांधी 12-13 अगस्त को वायनाड का दौरा करेंगे

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद अब आगामी 12 और 13 अगस्त को केरल स्थित अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड पहुंचेंगे। वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ''12-13 अगस्त को राहुल गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। वायनाड के लोग के इस बात से खुश हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई और उनकी आवाज संसद में लौट आई। राहुल जी सिर्फ एक सांसद नहीं, उनके परिवार के सदस्य हैं।'' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के तीन दिन बाद उनकी लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई।

केंद्र को भारत में सिंगल इंजन सरकार बर्दाश्त नहीं : सिब्बल

नई दिल्ली। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने संसद में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद केंद्र पर कटाक्ष करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें भारत में कहीं भी सिंगल इंजन (राज्य में किसी और दल की) सरकार बर्दाश्त नहीं है। संसद ने सोमवार को विवादास्पद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को मतविभाजन के बाद मंजूरी दे दी। यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। सिब्बल ने ट्वीट किया, दिल्ली एनसीटी (संशोधन विधेयक) 2023 को संसद ने पारित कर दिया। यह प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्वायत्तता को और कमजोर करने के मकसद से केंद्र को दिल्ली सरकार में नौकरशाहों की सेवाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्हें भारत में कहीं भी सिंगल इंजन सरकार बर्दाश्त नहीं है।

सांसद राघव चड्ढा पर लटकी एफआईआर की तलवार

नई दिल्ली। राज्यसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा द्वारा पेश किए एक प्रस्ताव पर फर्जीवाड़े के आरोप से नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में राज्यसभा चेयरमैन के द्वारा जांच में अगर फर्जीवाड़ा सही साबित होता है तो सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ऐसा उस स्थिति में किया जा सकता है जब चड्ढा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर फर्जी निकले। बीजद के सस्मित पात्रा और अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई सहित चार सांसदों ने शिकायत की थी कि दिल्ली सेवा विधेयक पर प्रस्तावित चयन समिति में उनकी सहमति के बिना उनका नाम शामिल किया गया था। इन आरोपों के सामने आने के बाद आप सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती है। राघव चड्ढा के ऊपर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा है और अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

सौरभ भारद्वाज से छीनकर आतिशी को दिए दो विभाग

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंगलवार को बड़ा बदलाव हुआ है। मंत्री आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग भी दिए गए हैं। सोमवार को ही राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ है। यह दोनों विभाग अभी तक सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को फाइल भेज दी है। कुछ महीने पहले ही दिल्ली सरकार के मंत्रीमंडल में फेरबदल किया गया था। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्रीमंडल में शामिल किया गया था। तब आतिशी को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट कल्चर व भाषा और टूरिज्म की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आम आदमी पार्टी में आतिशी ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है। आम आदमी पार्टी अपने आठ साल के कार्यकाल में जिन उपलब्धियों को सबसे ज्यादा बार गिनाती रही है उनमें शिक्षा का क्षेत्र सबसे ऊपर है और इसका बहुत बड़ा श्रेय आतिशी को जाता है।

इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 'इंडिया' गठबंधन के दलों का आभार

मणिपुर पर प्रधानमंत्री का 'मौन व्रत' तोड़ने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया : गोगोई

नईदिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और 'डबल इंजन' सरकार पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'मौनव्रत' तोड़ा जा सके।

गोगोई ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखते हुए यह सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पद पर क्यों बनाए रखा? उन्होंने दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मौन रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी छवि से लगाव है और वह अपनी सरकार की विफलताओं को सामने नहीं आने देना चाहते। कांग्रेस सांसद ने कहा, '' मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए 'इंडिया' गठबंधन के दलों को आभार प्रकट करते हैं।''

उनका कहना था, ''यह हमारी मजबूरी है कि हमें यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। यह संख्या को लेकर नहीं है, बल्कि मणिपुर के इंसाफ के लिए है।'' गोगोई ने कहा, ''यह अविश्वास प्रस्ताव हम मणिपुर के लिए लाए हैं। आज मणिपुर इंसाफ मांगता है, मणिपुर के युवा, महिलाएं इंसाफ न्याय हैं।'' उन्होंने दावा किया कि अगर आज मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है।, अगर मणिपुर में आग लगी है, मणिपुर विभाजित हुआ तो भारत में आग लगी है, भारत विभाजित हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा, ''हमारी मांग थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री बयान दें और यहां सदेश दिया जाए कि दुख की घड़ी में हम मणिपुर में उनके साथ थे।'' उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री ने मौन व्रत लिया। इसलिए हम इस अविश्वास प्रस्ताव लाए क्योंकि हम प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं।''

गौरव गोगोई ने पीएम मोदी से पूछे ये सवाल-

गोगोई ने सवाल किया, ''प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं

गए? उन्हें मणिपुर पर बोलने में लगभग 80 दिन क्यों लगे? जब बोले तो सिर्फ 30 सेकेंड के लिए बोले।'' उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक प्रधानमंत्री की तरफ से संवेदना का कोई शब्द नहीं है, न शांति की गुहार लगाई।

कांग्रेस नेता ने सवाल किया, ''प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा में चुनाव आने से पहले मुख्यमंत्री बदल दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री को ऐसा क्या आशीर्वाद दे रहे हैं?'' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को कबूल करना होगा कि मणिपुर में 'डबल इंजन' की सरकार विफल हो चुकी है। गोगोई ने कहा, ''150 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए।'' उन्होंने कहा, ''मणिपुर में कोई पहली बार हिंसा नहीं हुई है। लेकिन समाज के दो वर्गों के बीच बंटवारा हमने कभी नहीं देखा था।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''आज इस राजनीति से दो मणिपुर बन गए हैं। मैं (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी)वाजपेयी जी का संदेश मणिपुर के मुख्यमंत्री को देना चाहता हूं कि राजधर्म निभाया जाए। '' उन्होंने दावा किया कि अगर मणिपुर में वीडियो वायरल नहीं होता तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते चुप्पी साधे रहते। उन्होने आरोप लगाया, ''प्रधानमंत्री को छवि से लगाव है, इसलिए वह मौन रहें। प्रधानमंत्री मोदी के मौन रहने का दूसरा कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे हैं।

कांग्रेस नेता के अनुसार, जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर बंटवारा किया जाएगा तो पूर्वोत्तर में समस्याओं का समाधान नहीं होगा। गोगोई ने कहा, ''यह कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ज्यादा सत्ता को महत्व देता है?'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें और मणिपुर का दौरा करें और अपने साथ सभी दलों के लोगों को लेकर आएं। गोगोई ने कहा, ''आज आप (भाजपा) जितना भी नफरत फैलाएं, हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जगह-जगह मोहब्बत की दुकान खोलेंगे।''

सरकार को मिला बीजू जनता दल का साथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संसद में अपने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल का पहला प्रस्ताव है। हालांकि, इस बहस में नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का सरकार को साथ मिला है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि मैं आज केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता, भले ही हम एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के खिलाफ हैं। बीजेडी सांसद ने कहा कि मैं केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा के लिए किए गए कई कामों के लिए आभारी हूं, यही कारण है कि, किसी भी मामले में, मैं आज कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अपनी पार्टी और नेता की ओर से खुद को मनाने में असमर्थ हूं। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत के जबड़े से हार छीनने में माहिर है। वे अपना चेहरा बिगाड़ने के लिए अपनी नाक काटने में भी बहुत माहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री इस सदन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। यह सामान्य ज्ञान, तर्क, राजनीतिक समझ की अवहेलना करता है।

केंद्रीय संसदीय मंत्री ने लोकसभा में राहुल गांधी पर कसा तंज

राहुल अविश्वास प्रस्ताव पर बोलें सभी उनको सुनना चाहते हैं: जोशी

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद की लोकसभा में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो आज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, सरकार उनके भाषण का बेहद उत्साह के साथ इंतजार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री जोशी की टिप्पणी का बेहद तल्खी के साथ प्रतिवाद करते हुए कहा कि संसदीय मंत्री लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जो कुछ हुआ, उसका खुलासा कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

यह विवाद उस समय हुआ, जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दोपहर 12 बजे प्रस्ताव पर बहस शुरू करने के लिए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को बुलाया तो केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी अपनी सीट से उठे और कहने लगे कि उनकी जानकारी के अनुसार अध्यक्ष ओम बिड़का के कार्यालय को सुबह 11.55 बजे काग्रेस द्वारा एक पत्र देकर कहा गया कि गोगोई के स्थान पर राहुल गांधी बोलेंगे।

मंत्री जोशी ने आगे कहा, सर, पांच मिनट में ऐसा क्या हुआ सर? समस्या क्या है सर? हम राहुल गांधी को सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं।

मंत्री की टिप्पणी पर गौरव गोगोई ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या हमें सदन में यह भी बताना चाहिए कि आपके कार्यालय में क्या हो रहा है? आप इस सदन के संरक्षक हैं। क्या हमें यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं?

इस पर नाराज गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद गोगोई को टोकते हुए कहा कि कांग्रेस नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्हें जो कुछ भी बताना है, सदन को बताएं। इस पर गृहमंत्री अमित शाह की बातों का समर्थन करते हुए कहा, गोगोई सदन में इस तरह से प्रधानमंत्री और सभापति का नाम लेकर निराधार आरोप नहीं लगा सकते हैं।

इसके जवाब में गोगोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकसभा अध्यक्ष का सम्मान करती है और

उनके कार्यालय में कही गई हर बात की गोपनीयता का सम्मान करती है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, मेरा कार्यालय भी सदन का हिस्सा है। आपको कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिसका कोई वास्तव में आधार नही है।

केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि उन्होंने केवल वही खुलासा किया है, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में था। इस पर गोगोई ने कहा, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपको अपने कर्तव्यों को याद रखना चाहिए और अध्यक्ष के कार्यालय में जो कहा जाता है उसे प्रकट नहीं करना चाहिए।

राहुल गांधी गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे

संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इस सप्ताह का गुरुवार (10 अगस्त) अहम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से बहस में हिस्सा लेंगे। संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता उसी दिन बोलेंगे जिस दिन (10 अगस्त को) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को जवाब देने वाले हैं। उन अटकलों और कई रिपोर्टों के बाद जिसमें गांधी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की बहस का नेतृत्व करने का सुझाव दिया गया था। वहीं मंगलवार को विपक्ष की ओर से गोगोई की बहस शुरू होने पर लोकसभा में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।

खेल
प्रमुख समाचार

विश्व कप के लिए सभी टीमों को 28 सितंबर तक करना होगा टीम का ऐलान

नईदिल्ली। आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप की शुरुआत इस वर्ष भारत में 5 अक्टूबर से होने वाली है। ये विश्व कप का 13वां संस्करण होने वाला है। इस बार विश्व कप में दुनिया की कुल 10 बेहतरीन टीमें हिस्सा लेंगी। विश्व कप 2023 में हिस्सा लेने के लिए अब तक किसी भी टीम ने अपने सदस्यों की घोषणा नहीं की है। आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप के लिए सोमवार यानी सात अगस्त को ऑस्ट्रेलिया ने ही 18 सदस्यीय प्रारंभिक टीम का ऐलान किया है। भारत की टीम वर्तमान में वेस्ट इंडीज में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। वहीं भारत को आने वाले दिनों में आयरलैंड के साथ भी मुकाबले खेलने है। बीसीसीआई की नजर इन दोनों ही सीरीज के दौरान शानदार खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों पर होगी, जिनकी फॉर्म और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें विश्व कप टीम में शामिल किया जा सकता है।

बता दें कि आईसीसी ने ये भी ऐलान कर दिया है कि सभी टीमों को अपनी विश्व कप टीम की घोषणा किस दिन तक करनी है। आईसीसी के मुताबिक सभी टीमों को 28 सितंबर तक अपनी टीमों की घोषणा करनी होगी। विश्व कप में हिस्सा लेने वाली टीमों को अब सिर्फ 52 दिनों के भीतर ही अपनी टीमों की घोषणा करनी होगी। हालांकि टीमों के पास विकल्प होगा कि वो अपनी टीम की घोषणा करने के बाद उसमें फिर से परिवर्तन कर सकती है। आईसीसी ने सभी देश की टीमों को ये सुविधा दी है कि वो टीम का ऐलान करने के बाद भी अपनी टीम में बदलाव कर सकती है। आईसीसी ने ये मौका टीमों को दिया है। अगर कोई टीम टूर्नामेंट के दौरान भी टीम में परिवर्तन करना चाहती है तो उसे इसके लिए तकनीकी समिति से पहले अनुमति लेनी होगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 106 अंक टूटा निफ्टी 19,600 के नीचे

नईदिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले मिश्रित रुझानों के बीच हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। पीएसयू बैंकों ने अच्छी बढ़त के साथ बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि चुनिंदा आईटी शेयरों में भी तेजी रही। दूसरी ओर, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट आई। आज के कारोबर में बीएसई का सेंसेक्स 106 अंक टूटा। एनएसई के निफ्टी में भी 26 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 106.98 अंक यानी 0.16 फीसदी की गिरावट के साथ 65,846.50 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,057.53 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 65,752.63 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 26.45 अंक यानी 0.13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

अदाणी पोर्ट्स का जून तिमाही में नेट प्रॉफिट 80 फीसदी बढा

नईदिल्ली। अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लि. का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 80 फीसदी से अधिक बढ़कर 2,119.38 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से आमदनी बढ़ने से कंपनी का लाभ बढ़ा है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 की इसी तिमाही में कंपनी को 1,177.46 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन की कुल आय जून, 2023 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 6,631.23 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 5,526.19 करोड़ रुपये थी। कंपनी का खर्च घटकर आलोच्य तिमाही में कम होकर 4,065.24 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 4,438.32 करोड़ रुपये था।

5 साल में लग्जरी मकानों की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी

नईदिल्ली। महामारी लग्जरी मकानों (1.5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले) के लिए वरदान साबित हुई है क्योंकि इसके कारण इन मकानों की मांग और आपूर्ति कई गुना बढ़ गई है। जिससे इनकी कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट रिसर्च फर्म एनारॉक के मुताबिक देश के टॉप 7 शहरों में पिछले पांच वर्षों में इन मकानों की औसत कीमतों में 24 फीसदी वृद्धि दर्ज की है। जो अन्य मकानों की तुलना में सबसे अधिक है। एनारॉक के मुताबिक 7 शहरों में लग्जरी मकानों की औसत कीमत 12,400 रुपये वर्ग फुट थी, जो इस साल बढ़कर 15,350 रुपये वर्ग फुट हो गई है। लग्जरी मकान हैदराबाद में सबसे ज्यादा महंगे हुए है। हैदराबाद में 2018 में इन मकानों की औसत कीमत 7,450 रुपये थी, जो 2023 में 42 फीसदी बढ़कर 10,580 रुपये वर्ग फुट हो गई। हैदराबाद के बाद बेंगलूरू और मुंबई मेट्रो पोलिटन रीजन में लग्जरी मकानों की कीमतों में 27 फीसदी का इजाफा हुआ है।

एयरबस और बोइंग समय से पहले एयर इंडिया को डिलिवर करेंगे विमान!

नईदिल्ली। एयर इंडिया के बेड़े में बहुत जल्द ए350 और बी737 मैक्स विमान शामिल होने वाले हैं। मूल रूप से ये विमान चीन और रूसी वाहकों के लिए हैं। बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों (रूस और चीन) पर बैन ने टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइन के लिए इन विमानों की डिलिवरी की समयसीमा में तेजी ला दी है। ये विमान सितंबर से दिसंबर के बीच एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि एयर इंडिया ने फरवरी में 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होने वाले एयरबस 350 विमानों का पहला बैच मूल रूप से एअरोफ़्लोत के लिए था। हालांकि, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण इन्हें डिलिवर नहीं किया जा सका।

जीडीपी का आकार बड़ा होना अच्छी बात, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े

पी. एस वोहरा

देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे नंबर पर ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री के हाल ही के कई बयानों में साफ दिखाई पड़ी। अपनी हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान वहां कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में भी उन्होंने वर्ष 2028 से पहले भारत की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की बात कही। बीते दिनों भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर भी उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि उनकी सरकार के आगामी कार्यकाल में वह भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना देंगे। इस पक्ष पर एक अन्य सकारात्मक बात यह है कि अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी जुलाई, 2023 की रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वार्षिक विकास दर को 6.1 प्रतिशत अनुमानित किया है, जबकि आईएमएफ की पिछली रिपोर्ट में यह अनुमान छह प्रतिशत से कम का था। आईएमएफ की हाल ही की इस रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर तीन प्रतिशत आंकी गई है, जबकि अप्रैल की पिछली रिपोर्ट में यह 2.8 प्रतिशत आंकी गई थी।

आर्थिक विकास दर में यह सुधार निश्चित रूप से अमेरिका द्वारा अपने केंद्रीय बैंक को ऋण की सीमा के विस्तार पर सहमति तथा बैंकिंग नीतियों में आर्थिक सुधारों के कारण हुआ है। भारत के लिए एक अन्य सकारात्मक पक्ष यह है कि चीन में अप्रैल से जून वाली तिमाही में आर्थिक स्तर पर काफी गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि वहां का रियल एस्टेट सेक्टर मंदी के दौर से निकल रहा है। चीन में कोरोना महामारी के सभी प्रतिबंधों को उठाने के बावजूद अभी आर्थिक वृद्धि के लिए ज्यादा सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा है। इस परिदृश्य में पिछले तीन दशकों की भारत की आर्थिक यात्रा बहुत अविस्मरणीय

रही है। ज्ञात रहे कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र तीन खरब डॉलर की ही थी। पिछले एक दशक में मोदी युग के दौरान भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को जापान तथा जर्मनी को पीछे छोड़ना होगा।

तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना निश्चित रूप से हर भारतीय को गौरव तो महसूस करा रहा है, पर यह एक भ्रम को भी जन्म दे रहा है कि जीडीपी का आधार बढ़ने के साथ- साथ सभी भारतीयों की आय भी बढ़ेगी। जीडीपी में वृद्धि होने से भारत जैसे मुल्क में, जिसकी आर्थिक बागडोर पिछले दो-तीन दशकों से निजी क्षेत्र के कंधों पर है, आर्थिक असमानता का बहुत बढ़ना स्वाभाविक है। जरूरत इस बात की है कि हम जीडीपी के आकार को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक नीतियां में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर भी केंद्रित हों। इन दिनों भारत जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन गया है।

पर लगातार बढ़ती बेरोजगारी तथा महंगाई की दर ने समाज के 80 प्रतिशत तबके को आर्थिक रूप से परेशानियों में डाल रखा है। जीडीपी का आकार बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी भारत इस मामले में दुनिया में 125वें स्थान पर है। एक दशक पहले प्रति व्यक्ति आय करीब 80 हजार रुपये सालाना थी, जो अब बढ़कर 1.70 लाख रुपये से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि, अब भी 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें सरकार गरीब मानती है और उन्हें मुफ्त खाद्यान्न वितरण करती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों निर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि इत्यादि में सकारात्मक वृद्धि अंतत: जीडीपी का आकार बढ़ाती है। परंतु हम इस बात को क्यों स्वीकार नहीं कर पाते कि किसी कंपनी के मुनाफे में होने वाली वृद्धि का न्यूनतम हिस्सा ही काम करने वाले श्रमिकों की आय में जुड़ता है। इसी कारण भारत जैसे मुल्क में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई प्रति व्यक्ति आय को कैसे प्रभावित करती है, इस संदर्भ में इन दिनों टमाटर का उदाहरण बहुत समसामयिक है। इसलिए जीडीपी का आकार बढ़ाने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय को भी एक आदर्श मुकाम पर ले जाना आर्थिक नीतियों का मुख्य मकसद होना चाहिए। तभी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में तीसरे मुकाम पर पहुंचने के सपने को सभी भारतीय दिल से देखेंगे।

विपक्षी गठबंधन और प्रमुख क्षेत्रीय दलों में दरार चौड़ी

अजय सेतिया

चार बड़े क्षेत्रीय राजनैतिक दलों ने भाजपा विरोधी इंडिया गठबंधन (पूर्ववर्ती यूपीए) के इस आरोप की हवा निकाल दी है कि भाजपा या मोदी सरकार देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये चार दल हैं वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी। ये चारों बड़ी पार्टियां हैं, दो पार्टियों की दो राज्यों में सरकार है, और बाकी दो दलों की अपने अपने राज्यों में सरकार रही है। वाईएसआर कांग्रेस की न सिर्फ आंध्र प्रदेश में सरकार है, बल्कि उसके लोकसभा में 22 सांसद हैं, और वह द्रमुक और टीएमसी के साथ ही लोकसभा में दूसरे नंबर की पार्टी है। बीजू जनता दल की न सिर्फ उड़ीसा में सरकार है, बल्कि लोकसभा में उसके 12 सांसद हैं। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, और लोकसभा में उसके दस सांसद हैं। चौथी पार्टी तेलुगु देशम की आंध्र प्रदेश में सरकार रही है और उसके लोकसभा में तीन सांसद हैं। इन चारों दलों ने मोदी सरकार का समर्थन करके कांग्रेस के इस आरोप को निर्मूल साबित कर दिया है कि भाजपा या मोदी सरकार से भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इन चारों दलों ने दिल्ली सेवा बिल का समर्थन करके कुछ दिनों से बनाई जा रही इस धारणा को भी खत्म कर दिया है कि यह कानून या इस कानून के माध्यम से मोदी सरकार देश के संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है। अगर यह बिल किसी भी तरह संघीय ढांचे के लिए खतरा होता तो ये चारों क्षेत्रीय दल बिल का समर्थन नहीं करते। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए सही कहा कि दिल्ली जब राज्य ही नहीं है, यह केंद्र शासित क्षेत्र है, तो यह बिल संघीय ढांचे पर खतरा कैसे हुआ। सुप्रीमकोर्ट इस क़ानून पर क्या रूख अख्तियार करता है, यह देखना होगा। वैसे सुप्रीमकोर्ट सुविधा के अनुसार अपने फैसले बदलता रहता है, जिस कारण सुप्रीमकोर्ट की शुचिता पर भी सवाल उठते रहे हैं, जैसे राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे देकर सुप्रीमकोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व क़ानून के संबंध में अपने 2013 के फैसले को ही निष्प्रभावी बना दिया है। यूपीए से इंडिया बने गठबंधन का मूल आधार ही यह है कि भाजपा की सरकार लोकतंत्र को अधिनायकवाद में बदल रही है, और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वायत संस्थाओं पर नियन्त्रण कर रही है या उन्हें खत्म कर रही है। ब्रिटेन और अमेरिका की यात्राओं के दौरान राहुल गांधी के भाषणों का लब्बोलुवाब यही था कि न्यायपालिका तक सरकार के दबाव में है। जब उन्हें मानहानि के केस में अपराधी ठहराया गया और जनप्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 8 (3) के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई, तो इसे भी उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला था, उन पर सवाल उठाए थे, इसलिए उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। उनका यह बयान ऑन रिकार्ड है। उनके इस बयान के आधार पर लोकसभा सचिवालय को सुप्रीमकोर्ट में केस दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता किसी दुर्भावना या उनके लोकसभा में भाषण के कारण खत्म नहीं की थी। इसमें सत्ताधारी पार्टी, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा सचिवालय की कोई भूमिका ही नहीं थी। जन प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 8 (3) के मुताबिक़ उनकी सदस्यता खुद ब खुद निरस्त हो गई थी, लोकसभा सचिवालय का काम संबंधित विभागों को सिर्फ सूचित करना था, और उसने वही किया, जिसे मीडिया और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की तत्परता कह कर देश को गुमराह किया था।

सवालों और शंकाओं से घिरे शरद पवार

समीर चौगांवकर

एक अगस्त को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुणे में मंच साझा किया था। उस समय विपक्ष ने शरद पवार पर सवाल उठाया था। लेकिन अब अमित शाह ने अपने पुणे दौरे के दौरान न केवल अजित पवार की जमकर प्रशंसा की है बल्कि शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल से भी गुप्त मुलाकात की है। इसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि जयंत पाटील और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस दोनों ने ऐसी किसी मुलाकात से इंकार किया है।

रविवार को पुणे में अमित शाह ने कहा कि अजीत पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद मैं उनके साथ मंच पर पहली बार कार्यक्रम कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, दादा आप बहुत समय बाद सही जगह पर बैठे हैं। यह जगह सही थी लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अमित शाह के इस बयान के बारे में कहा जा रहा है कि अभी महाराष्ट्र के कई बड़े नेता भी मोदी के समर्थन में एनडीए में साथ आ सकते हैं, शायद इसमें सबसे बड़ा नाम शरद पवार का हो। अजीत पवार ने भी अमित शाह की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि अमित शाह गुजरात से आते हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र ज्यादा पसंद है। अजित पवार ने कहा कि %अमित शाह महाराष्ट्र के दामाद हैं। दामाद को ससुराल वाले ज्यादा प्यारे लगते हैं। अजीत पवार के इस बयान ने विपक्ष के कान खड़े कर दिए हैं।

दरअसल विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद भी शरद पवार द्वारा मोदी के साथ मंच साझा करने से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की बैचेनी बढ़ी है। विपक्षी एकता की पहली बैठक 23 जून को पटना में और दूसरी बैठक बेंगलुरू में 18 जुलाई को हुई थी। विपक्षी एकता की तीसरी बैठक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मेजबानी में कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से मुम्बई के ग्रेंड हयात होटल में 31 अगस्त और 1 सिंतबर को होने की संभावना है। हालांकि बैठक की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है।

मुम्बई में होने वाले विपक्षी दलों के महाजुटान के पहले शरद पवार के रूख को लेकर सभी आशंकित है। खबर है कि महाराष्ट्र में विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर कांग्रेस के विजय वेट्टीवार को नियुक्त करने के निर्णय से शरद पवार असहमत थे। शरद पवार चाहते थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट के बाद भी कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास रहने दे। शरद पवार ने इसके लिए अपने करीबी जितेन्द्र आव्हाड का नाम आगे बढ़ाया था और उसके लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा था। लेकिन कांग्रेस ने विधानसभा में सबसे बड़ा दल होने के नाते शरद पवार की मांग को ठुकरा दिया था और अजीत पवार की बगावत के बाद खाली हुए विपक्ष के नेता का पद अपने पास रखने का निर्णय लिया था। कांग्रेस द्वारा विपक्ष के नेता का पद अपने पास रखने के निर्णय के बाद शरद पवार ने कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि विपक्ष का नेता मराठा और पश्चिम महाराष्ट्र से होना चाहिए जिससे अजीत पवार को चुनौती दी जा सके। कांग्रेस ने शरद पवार की यह सलाह भी नहीं मानी और विदर्भ के ओबीसी नेता विजय वेट्टीवार को विपक्ष का नेता बना दिया। शरद पवार इस बात पर नाराज हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी विदर्भ से आते है और विपक्ष का नेता भी विदर्भ से है। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन नहीं बन रहा है।

इसके अलावा कांग्रेस और शरद पवार के बीच मतभेद की वजह अब तक महाविकास अघाड़ी में शामिल रही समाजवादी पार्टी का गठबंधन से बाहर होना है। समाजवादी पार्टी अघाड़ी से अलग होकर किसान नेता एवं पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व में बने तीसरे गठबंधन में शामिल हो गयी है। कांग्रेस को इस बात का शक है कि राजू शेट्टी के तीसरे मोर्चे को पर्दे के पीछे से शरद पवार का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र में पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने %प्रागतिक विचार मंच% के नाम से एक नया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में राज्य के अधिकांश छोटे दल शामिल हो गये हैं। इस गठबंधन की वजह से राज्य में मौजूद एमवीए को नुकसान होना तय है। राजू शेट्टी के नए मंच में स्वाभिमानी किसान संघ, शेकाप, स्वराज्य पार्टी, आम आदमी पार्टी, लाल निशान ग्रुप, बहुजन विकास अघाड़ी, समाजवादी पार्टी, जनता दल, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीआई (एम) आदि दलों ने शामिल होने की तैयारी दर्शाई है। कांग्रेस नेताओं को इस बात का शक है कि राजू शेट्टी के इस प्रयोग के पीछे शरद पवार है और शरद पवार राजू शेट्टी को आगे कर कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि इसके पीछे राष्ट्रवादी पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाना हास्यापद है। कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे भी शरद पवार को शक की नजर से देख रहे हैं। शरद पवार ने घोषणा की थी कि अजीत पवार के साथ जाने वाले विधायकों को सबक सिखाने के लिए वह उद्धव को साथ लेकर पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे लेकिन नासिक के येवला में रैली करने के बाद शरद पवार ने आगे कोई रैली न करने का निर्णय लिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नासिक के येवला की रैली से बागियों पर निशाना साधा था। हालांकि, येवला की रैली के बाद शरद पवार ने कोई रैली नहीं की और न ही अजीत पवार गुट पर निशाना साधा। इसके अलावा शरद पवार और अजित पवार गुट के विधायक मानसून सत्र में एक साथ चर्चा करते नजर आए और शरद पवार गुट के विधायकों ने अजित पवार के साथ बैठक भी की थी। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे भी शरद पवार से जानना चाहते हैं कि वो अजित पवार गुट के खिलाफ कोई ठोस रुख क्यों नहीं अपना रहे हैं?

महाराष्ट्र भाजपा के एक बड़े नेता का कहना है कि शरद पवार फिलहाल दोनों नावों पर पैर रखकर चल रहे हैं। वह अंदरखाने अजित के साथ हैं और ऊपरी तौर पर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। शरद पवार मंझे हुए मराठा नेता हैं। समय आने पर जिसका पलड़ा भारी होगा, उसकी नाव में शामिल हो जाएंगे। शरद पवार की राजनीति को करीब से देखने वाले उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों इस बात से वाफिक हैं कि शरद पवार कभी भी कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए सियासी गलियारों में यह सवाल तैर रहा है कि शरद पवार की अगली गुगली क्या होगी?

महाराष्ट्र में एनसीपी भले ही टूट गई हो लेकिन अजित पवार की शरद पवार से मुलाकात और महाराष्ट्र विधानसभा में अजित पवार गुट के नेता सुनील तटकरे और शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल की मुलाकात और बैठकों के कारण एनसीपी आपस में मिली हुई नजर आ रही है। भाजपा की भी पूरी कोशिश महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले या बाद में शरद पवार को अजित पवार के साथ खड़ा करने की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि अजित पवार के मुख्यमंत्री बनने पर शरद पवार भाजपा का विरोध छोड़कर अजित पवार के साथ हाथ मिला लेंगे। शरद पवार और अजीत पवार दोनों एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कयास कोई कुछ भी लगाये लेकिन शरद पवार क्या कर रहे हैं और क्या निर्णय लेनेवाले हैं, यह उनके अलावा कोई नहीं जानता।

प्रसंग

बेकार भूमि को अन्नपूर्णा बनाता जेसीबी मैन

माउंटेन मैन दशरथ माँझी के हौसले की कहानी से सभी वाकिफ हैं, जिन्होंने अकेले पहाड़ का सीन चीरकर रास्ता तैयार किया। अब एक और शख्स से मिलिए, जिसे लोग जेसीबी मैन कहते हैं। यह हैं फतेहपुर के अमौली ब्लॉक में भरसा के मजरे केवटरा गाँव के 75 वर्षीय भावन निषाद नोन नदी किनारे बसे इस गाँव में भावन ने 25 वर्षों में 50 बीघा ऊबड़-खाबड़ जमीन समतल कर उसे अन्नपूर्णा बना दिया। आज भी बूढी काया में फौलादी इरादे समेटे भावन नदी किनारे और भी जमीनों को खेती के योग्य बनाने में जुटे हैं, गीता के इस उपदेश को आत्मसात् करते हुए कि सुखी रहना है तो निष्काम भावसे कर्म करो।

भावन के तैयार किए खेतों में अब गेहूँ, चना व सरसों की फसल लहलहा रही है। नदी की ऊबड़-खाबड़ जमीन पर फावड़ा चलाते हुए 75 साल के बूढ़े को देखकर हर किसी के मन में सवाल उठता है कि इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों और किसके लिए? इसका जवाब भावन देते है, पत्नी की मौत के बाद अकेला हो गया तो सोचा कि गाँव के लिए ही कुछ किया जाए। मेरी समतल की गई जमीन से सैकड़ों लोगों का पेट भरता है, क्या यह पुण्य नहीं है।

प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र निषाद कहते हैं कि भावन को इससे मतलब नहीं है। कि जमीन किसकी है और इसकी पैदावार कौन लेगा। वह निष्काम भाव से जमीन समतल करते हैं। जिसका मालिकाना हक होता है, वह जमीन पर फसल तैयार कर पैदावार लेता है। इस मेहनत के एवज में जेसीबी मैन को लोग केवल दोनों पहर की रोटी दे देते हैं न भी दें तो वह खुद बनाकर पेट भरते हैं।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

2008 दक्षिण ओसेशिया और जॉर्जिया में रूस और जॉर्जिया के बीच युद्ध जारी है। रूसी जेट ने दक्षिण ओसेशिया के बाहर, गोरी शहर में सैन्य ठिकानों पर हमला किया।

2009 डबल-विवाह का एक उदाहरण डबलिन में न्याय, समानता और कानून सुधार विभाग के बाहर होता है।

2011 ऑस्ट्रेलियाई कैबिनेट के पहले सार्वजनिक रूप से समलैंगिक सदस्य पेनी वोंग ने घोषणा की कि उनका साथी एक बच्चा होगा।

2013 आतंकवादी खतरों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तानी शहर लाहौर में अपने वाणिज्य दूतावास से राजनयिकों को हटा दिया।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

ध्यानबिन्दुपनिषद् (भाग-6)

गतांक से आगे...

यह उड्डियान बन्ध मृत्यु के निमित्त उसी तरह है, जैसे गजराज के लिए सिंह निमित्त बनता है। जिसमें शिरोनभ (आकाश) से उत्पादित जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही अवरुद्ध कर लिया जाता है, उसे जालन्धरबन्ध कहा गया है। इससे कर्मबन्धन और पापजन्य दु:खों का नाश होता है। जालन्धर बन्ध करते समय कण्ठ को सिकोड़ा जाता है, जिससे वायु की गति रुक जाती है और अमृत के अग्नि में गिरने की सम्भावना नहीं रहती। खेचरी मुद्रा उसे कहते हैं, जिसमें जिह्वा को उल्टाकर कपाल कुहर में प्रविष्ट किया जाए और अपनी दृष्टि को दोनों भौंहों के बीच स्थिर रखा जाए। इसके सिद्ध हो जाने से निद्रा, क्षुधा, पिपासा नहीं सताती और न व्याधि एवं मृत्यु का भय ही रहता है।

जो खेचरी मुद्रा का ज्ञाता है, उसे न तो मूर्च्छा होती है, न रोग उसे कष्ट देते हैं और न ही वह कर्मों से ही लिए हो पाता है। खेचरी मुद्रा से जिसका चित्त आकाश में विचरण करने लगता है और जिसकी जिह्वा भी अन्तरिक्षगामिनी हो जाती है, ऐसा साधक काल के बन्धन से बँधता नहीं है। इसलिए यह खेचरी मुद्रा योगियों द्वारा प्रशंसनीय है। इस मुद्रा द्वारा जिसने तालु के छिद्र को अवरुद्ध कर दिया है, उसके द्वारा स्त्री समागम से भी वीर्य का क्षरण नहीं होता और जब तक वीर्य शरीर में विद्यमान रहता है, तब तक मौत के भय की सम्भावना ही कैसी?

खेचरी मुद्रा में रहते हुए वीर्य का क्षरण सम्भव नहीं, फिर भी किसी तरह यदि वीर्य स्खलित होकर योनि में चला जाए, तो उसे हठशक्तिपूर्वक योनिमण्डल से पुन: ऊपर की ओर खींच लेते हैं। वह वीर्य भी सफेद और रक्त वर्ण दोनों तरह का होता है। सफेद वर्ण वाले को शुक्र और रक्त वार्ण वाले को महारज कहा गया है। मूँगे की तरह वर्ण वाला रज (योगी के) योनिस्थान में विद्यमान है और शुक्ल वीर्य चन्द्रस्थान में है, पर इन दोनों के एक होने की सम्भावना बड़ी दुर्लभ है। वीर्य को शिवरूप और रज को शक्तिरूप कहा गया है, वीर्य ही चन्द्रमा और रज ही सूर्य है।

इन दोनों के संयुक्त होने पर परम देह की प्राप्ति होती है। वायु को शक्ति से संचालित किये जाने से रज अन्तरिक्ष की ओर प्रेरित होता है और सूर्य से संयुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। शुक्लवर्ण वीर्य चन्द्रमा से और रज सूर्य से युक्त है। इन दोनों की समरसता का जो ज्ञाता है, वही योगवेत्ता है।

क्रमश: ...

भारत छोड़ो आंदोलन दिवस

रमेश सर्राफ धमोरा

9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। यह वह आंदोलन था जिसमें पूरे देश की व्यापक भागीदारी रही थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मशहूर घटना काकोरी कांड के ठीक सत्रह साल बाद हुये इस आंदोलन ने देखते ही देखते ऐसा स्वरूप हासिल कर लिया कि अंग्रेजी सत्ता के दमन के सभी उपाय नाकाफी साबित होने लगे थे। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधीजी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ शुरू हुए आंदोलन के थोड़े ही समय बाद गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ताओं ने हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन को जिंदा रखा।

1942 का आंदोलन 1920, 1921, 1930, 1940-41 के आंदोलनों से काफी भिन्न था। इसी कारण सुभाष बाबू ने कहा कि 1942 में पेसिव रजिस्टेन्स के युग का अंत होकर एक्टिव रजिस्टेन्स का सूत्रपात हुआ। राजनारायण मिश्र, महेंद्र चौधरी, लेना प्रसाद, मांतिगिनी, हाजरा, चापेकर बंधुओं, खुदीराम, कन्हाईलाल, करतार सिंह, रामप्रसाद बिस्मित, अशफकाउल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों के अविस्मरणीय योगदान ने आजादी की राह काफी सरल बना दी। गांधीजी का 'करो या मरो' अत्यन्त ही शक्तिशाली मंत्र था। शब्द शास्त्र के कुशल शिल्पकार बापू के मंत्र का भी देशव्यापी असर पड़ा और यह नारा बाद में ध्येय मंत्र बन गया। 6 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से बिस्मिल के नेतृत्व में हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ के दस जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड किया था, जिसकी यादगार ताजा रखने के लिए पूरे देश में हर साल 9 अगस्त को काकोरी काण्ड स्मृति-दिवस मनाने की परम्परा भगत सिंह ने प्रारंभ कर दी थी और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे। गांधी जी ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत 9 अगस्त 1942 का दिन चुना था। यह आंदोलन गांधी जी की सोची-समझी रणनीति का ही हिस्सा था। दरअसल, दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी से सभाषचंद्र बोस ने आजाद हिन्द फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांप लिया और 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया। 9 अगस्त 1942 के दिन इस आंदोलन को लाल बहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने एक बड़ा रूप दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1942 में मरो नहीं, मारो का नारा दिया जिसने क्रान्ति की दावानल को पूरे देश में प्रचण्ड किया। 19 अगस्त, 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। 900 से ज्यातदा लोग मारे गए, हजारों लोग गिरफ्तार हुए इस आंदोलन की व्यूह रचना बेहद तरीके से बुनी गई थी। चूंकि अंग्रेजी हुकूमत दूसरे विश्व युद्ध में पहले ही पस्त हो चुकी थी और जनता की चेतना भी आंदोलन की ओर झुक रही थी, लिहाजा 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था।

तोशाखाना तो बहाना है, इमरान को चुनाव से दूर हटाना है

बिक्रम उपाध्याय

पाकिस्तान में सरकारी खजाने को तोशाखाना कहते हैं और उस तोशाखाना से सामान गायब करने या नियमों के विरुद्ध जाकर तोहफों को हथिया लेने के पहले आरोपी नहीं है इमरान खान। नवाज शरीफ से लेकर आसिफ जरदारी तक पर भी इस तरह के कई आरोप हैं। पर सजा इमरान खान को हुई तो इसका एक ही मतलब है कि मौजूदा हुकूमत और फौज किसी तरह से अगले चुनाव में तहरीक ए इंसाफ पार्टी और उसके चेयरमैन इमरान खान को बाहर रखना चाहती है। इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है, इसका मतलब है कि वह अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। पर यह खेल मौजूदा सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की ऊंची अदालतों से इमरान खान कई बार अपना बचाव कराते रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल को उनका संरक्षक ऐसे ही नहीं कहा जाता।

वैसे, तोशाखाना का मामला है बड़ा दिलचस्प। प्रधानमंत्री के नाते विदेशों से इमरान खान को जो भी तोहफे मिलते, घर में बैठी उनकी बेगम बुशरा बीवी उसको ठिकाने लगा देती। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के अनुसार तोहफे सरकारी तोशाखाना में जमा होने की बजाए सीधे प्रधानमंत्री आवास में आते और बुशरा बीवी तय करती कि किसको खजाने में जमा करना है और किसे अपने पास रख लेना है। फिर नियमों की खानापूर्ति की जाती। बुशरा बीवी की दोस्त फराह गोगी तोहफे को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने जाती और सीधे कैश बैग में भरकर स्पेशल विमान से लेकर आती थी। तब न सेना उनसे पूछती थी और न कोई अन्य सरकारी महकमा। तोशाखाना का सबसे बड़ा घोटाला तब सामने आया जब दुबई के एक व्यापारी उमर फारूक जहूर ने यह दावा किया कि इमरान खान को सउदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो हीरो से जड़ित घड़ी दी थी, उसे उन्होंने 20 लाख डॉलर में इमरान खान से खरीद लिया है। उसने उस तोहफे को बकायदा अपने घर से लाइव जीओ टीवी को दिखाया। जहूर ने उस हीरे जड़ी घड़ी का बाजार में अंतरराष्ट्रीय मूल्य कई गुणा अधिक बताया था। लेकिन इमरान खान ने यह दावा किया था कि उनके लोगों ने वह घड़ी तोशाखाना से खरीद कर यहीं एक स्थानीय दुकानदार को बेच कर नियमानुसार 20 प्रतिशत पैसा जमा करा दिया था। इस घोटाले के बाद तो तोशाखाना से मंगाये और गायब किए सामानों की लंबी फेहरिस्त आ गई। उनमें कुछ जेवर, एक सोने की परत वाली पिस्तौल, करतार साहिब रूट के उद्घाटन के समय सिखों द्वारा दिए गए सोने के कलश इत्यादि तोशाखाना से गायब हुई चीजों में शामिल मिले।

इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले दर्ज कराया गया। पर इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने निचली अदालत से केस की सुनवाई के लिए कहा और लगभग डेढ साल बाद अब सेशन कोर्ट ने इमरान को सजा सुनाया है। भ्रष्टाचार के मामलों में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रियों के जेल जाने का इतिहास बहुत लंबा है। इमरान खान से पहले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, शाहिद खक्कान अब्बासी, जुल्फिकार अली भुट्टो और हुसैन शाहिद सुहरावर्दी भी जेल जा चुके हैं। पर इनमें से सभी बाद में ऊपरी अदालत से बरी भी कर दिए गए। इसलिए इमरान खान को भी तोशाखाना मामले में जमानत मिल जाएगी और समय के साथ केस भी खत्म होने की संभावना है। पर इमरान फिलहाल केसों से निजात नहीं पा सकेंगे। क्योंकि उन पर केवल तोशाखाना का केस ही नहीं है। जज को धमकाने से लेकर सेना के खिलाफ विद्रोह पैदा करने तक का मामला चल रहा है। इस समय उन पर 180 मुकदमें चल रहे हैं, जिनमें से किसी न किसी मुकद्दमें में रोज ही उनकी पेशी होती है। मौजूदा हुकूमत को इमरान खान को जेल में डालने से दो मतलब सधते हैं। जेल में रहकर इमरान खान रोजाना मीडिया में नहीं आ सकते जिससे चुनाव में उनकी भागीदारी खत्म या कम की जा सकती है। दूसरा, खुद इमरान को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के फैसलों को कुछ दिन और बरकरार रखकर उनको भी चुनावी समर से दूर किया जा सकता है। पाकिस्तान में चुनाव कायदे से अक्टूबर या नवंबर में होने चाहिए, पर फिलहाल इसमें देरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नये वोटर लिस्ट के हिसाब से चुनाव कराए जाने का ऐलान किया है जिसको तैयार करने में कम से कम चार पांच महीने का समय मिल जाएगा।

पाकिस्तान में चुनाव हमेशा एक केयरटेकर सरकार की देखरेख में किया जाता है। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मौजूदा सरकार 9 अगस्त को काम काज छोड़ कर एक निगरा सेटअप को सत्ता सौंप सकती है। निगरा यानी कामचलाऊ सरकार की जिम्मेदारी जिसे भी दी जाएगी, उसकी पहली कोशिश तब तक चुनाव टालने की होगी, जब तक कि इमरान खान को एक दो और मामले में सजा नहीं हो जाती और यह निश्चित नहीं कर लिया जाता कि खान और उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। इस फैसले में फौज की भी सहमति है। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में तहरीक ए इंसाफ द्वारा सेना के प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाने के बाद से सेना इमरान खान को निबटाने में लगी हुई है। उस दिन के सभी आरोपियों को आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाने का फैसला फौज और सरकार ने कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ भी आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इसमें अभी चीफ जस्टिस बांदियाल अडंगा लगाए हुए हैं। वह सामान्य नागरिकों के मामले आर्मी कोर्ट में चलाए जाने के खिलाफ हैं और यह ऐलान कर चुके हैं कि वह सेना को ऐसा करने से रोकेंगे।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और तमाम इनके सहयोगी इस इंतजार में हैं बांदियाल की सुप्रीम कोर्ट से बिदाई हो तो फिर इस मामले में तेजी लाई जाए। बांदियाल का कार्यकाल 16 सितंबर तक है। उसके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। जस्टिस ईसा का इमरान खान के साथ पहले से ही एक द्वंद्व चल रहा है। प्रधानमंत्री रहते इमरान खान ने जस्टिस ईसा और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चलवाया था। जस्टिस ईसा ने भी इमरान खान की लंदन स्थित प्रापर्टी के बारे में तमाम जानकारियां दी थी और यह आरोप लगाया था कि वे सारी संपत्तियां ब्लैक मनी से खरीदी गई हैं। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि जो सहुलियतें मौजूदा चीफ जस्टिस बांदियाल के रहते इमरान खान को मिल रही हैं वे काजी फैज ईसा के समय नहीं मिल सकती। पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने इस बात की भी तैयारी कर ली है, यदि इमरान खान को निबटाने में देरी भी हो तो भी पाकिस्तान के शासन प्रशासन का काम काज प्रभावित ना हो। एक अलग विधेयक लाकर निगरा हुकूमत को वे तमाम अधिकार दे दिए गए हैं जो एक नियमित सरकार के पास होते हैं। यानी उनको सभी प्रकार के आर्थिक व प्रशासनिक फैसले लेने के लिए अधिकार संपन्न कर दिया गया है।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में निशिकांत दुबे ने विपक्ष को घेरा

■ लालू यादव को हमने जेल नहीं भेजा

नई दिल्ली। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हमें लगा था कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन लगता है वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे, हो सकता है कि वह देर से सोकर उठे होंगे। मणिपुर पर दुबे ने कहा कि मैं खुद मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे रिश्तेदार जो सुरक्षाबल में उच्च पद पर थे, वह उग्रवादी हमले में घायल हुए थे।

निशिकांत दुबे ने विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में बैठे कुछ ही लोग इंडिया की फुल फॉर्म बता पाएंगे। दुबे ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं लेकिन इसके बावजूद केंद्र में गठबंधन कर रही हैं। लालू यादव को हमने जेल नहीं भेजा, कांग्रेस ने जेल भेजा। शरद पवार को किसने बर्खास्त किया? जदयू को सबसे ज्यादा फंड मैंने दिलवाया। शेख अब्दुल्ला को जेल में कांग्रेस ने बंद किया। सीपीएम देशद्रोही पार्टी के साथ है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि हम 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे।

दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर सिर्फ रोक लगाई है और अभी तक फैसला नहीं दिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे, हां वो ओबीसी वर्ग से क्यों माफी मांगेंगे। दूसरा वह कहते हैं कि वह सावरकर नहीं है...आप कभी सावरकर बन भी नहीं सकते। सावरकर ने 28 साल जेल में बिताए, आप कभी सावरकर नहीं बन सकते। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर तंज कसते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष ये देखना चाहता है कि कौन-कौन साथ है।

निशिकांत दुबे का सोनिया गांधी पर तंज

निशिकांत दुबे सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ये क्यों लाया गया है? सोनिया जी (गांधी) यहां बैठी हैं। मुझे लगता है कि उन्हें दो काम करने होंगे - बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। यही इस प्रस्ताव का आधार है। वहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान डीएमके सांसद टीआर बालू ने कहा कि मणिपुर के अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मारा गया है। 143 लोग मारे गए हैं। 65,000 लोग राज्य छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की सड़कों पर दो महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और नग्न घुमाया गया... मुख्यमंत्री असहाय हैं। पीएम संसद में नहीं आ रहे हैं और वह राज्य में नहीं गए हैं वहीं, इंडिया पार्टियां वहां गईं और समझ गईं कि क्या हुआ है।

पीयूष गोयल के खिलाफ विपक्षी दलों ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों के नेताओं ने उन्हें देशद्रोही कहकर संबोधित करने के लिए सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि सदन में माफी से कम कुछ भी नहीं चलेगा। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है।

रमेश ने ट्वीट कर कहा कि मंगलवार को 13.00 बजे, राज्यसभा में भारतीय दलों के नेताओं ने विपक्ष को देशद्रोही कहकर संबोधित करने के लिए सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सदन में उनके लिए माफी से कम कुछ भी नहीं है। वहीं, पीयूष गोयल ने कहा कि आज सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा उठाया। एक अमेरिकी अखबार ने एक गंभीर मुद्दे को उजागर किया है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा अखबार बताया है। इस अखबार ने इन अहंकारी नेताओं के गठजोड़ का खुलासा किया है, इनका रिश्ता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से खोजा जा सकता है।

पीयूष गोयल ने आगे कहा कि पहले हम सोचते थे कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही चीन और रूस के इशारे पर चलती है, लेकिन फिर हमें इसकी भनक लग गई कि 2007-08 में कांग्रेस के स्थायी युवा नेता भी चीन के इशारे पर चले। यूपीए और कांग्रेस के शासनकाल में चीन के साथ आर्थिक व्यापार के साथ-साथ देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई. अब न्यूज़क्लिक का मुद्दा उन लोगों पर गंभीर सवाल उठाता है जो लोकतंत्र की बात करते थे और आरोप लगाते थे कि भारत स्वतंत्र प्रेस को लेकर परेशानी का सामना कर रहा है। अब यह स्पष्ट है कि वे सभी पेड मीडिया थे जिन्होंने झूठे आख्यानों का प्रचार किया जिसके लिए कांग्रेस के नेता, नेता टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इसकी गारंटी देंगे।

विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने का रहेगा मलाल : किरेन रिजिजू

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने कहा कि गठबंधन को इंडिया नाम देने से कुछ नहीं होगा, जबकि आप वास्तव में भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2014 से पहले, पूर्वोत्तर के कई लोगों को दिल्ली और देश के अन्य प्रमुख शहरों में नस्लीय भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा था। 2014 के बाद हालात बदले और आजादी के बाद पहली बार गुवाहाटी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई। इस बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया कि पुलिस पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए काम करना और उनके मुद्दों को समझना ही हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी ने इस तरह पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में रहने वाले लोगों का भरोसा जीता है।

किरेन रिजिजू ने दावा किया कि जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कोई उग्रवाद पुनरुत्थान नहीं हुआ है और 8,000 से अधिक आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। एएफपीए का कुल कवरेज क्षेत्र 75त्न कम कर दिया गया है। जब आप मणिपुर के बारे में बात करें तो हर बात को ध्यान में रखें, नहीं तो आप सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत समय पर और गलत तरीके से यह अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विपक्षी दलों को अफसोस होगा। दुनिया भर में भारत की छवि सुधरी है। देश-विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों का मानना है कि नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक इस देश को एक विकसित राष्ट्र बना देगा। ऐसे समय में वे ऐसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला करते हैं। भाजपा नेता ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की खराब नीतियों की वजह से मणिपुर का यह हाल हुआ है।

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर पीएम मोदी की गरज सुनेंगे अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन। अमेरिकी सांसदों का एक द्विदलीय समूह 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए भारत आ रहा है। द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना और सांसद माइकल वाल्ट्ज कर रहे हैं। बता दें, दोनों अमेरिकी सदन में देश विशेष के सबसे बड़े द्विदलीय गठबंधन %कांग्रेसनल कॉकस ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन्स% के सह-अध्यक्ष हैं।

अमेरिका के सांसद लाल किले का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री भारत के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा यह लोग हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में व्यापार, तकनीकी, सरकार और बॉलीवुड से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही महात्मा गांधी को समर्पित ऐतिहासिक स्मारक राजघाट का दौरा करेंगे।

बता दें, भारत आने वालों में खन्ना और वाल्ट्ज के अलावा सांसद डेबोरा रॉस, कैट कैममैक, श्री थानेदार, जैस्मीन क्रॉकेट के साथ-साथ रिच मैककॉर्मिक और एड केस भी शामिल हैं। हालांकि, सांसद खन्ना के लिए भारत आना और सांसदों से थोड़ा ज्यादा खास है। दरअसल, उनके दादा अमरनाथ विद्यालंकार एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने गांधीजी के साथ चार साल जेल में बिताए थे और बाद में भारत की पहली संसद का हिस्सा बने थे।

खन्ना ने कहा कि इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष के रूप में भारत में एक द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हम इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा करेंगे।

इसके अलावा, अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आएंगे। उनकी यात्रा से पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने अतीत में नियमित रूप से भारत के साथ मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया है और भविष्य में भी ऐसा करेगा। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पत्रकारों से कहा कि हम नियमित रूप से उन देशों के साथ मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को उठाते हैं जिनके साथ हम जुड़ते हैं, हमने पहले भी भारत के साथ ऐसा किया है और हम भविष्य में भी ऐसा करेंगे।

मिलर से पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति जो बाइडन अपनी आगामी भारत यात्रा के दौरान देश में कथित ईसाई उत्पीड़न के संबंध में भारत से बात करेंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईसाइयों और हम किसी भी धार्मिक समूह के उत्पीड़न का विरोध करते हैं, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो।

राघव चड्ढा का संजय सिंह ने किया बचाव, कहा-

गृहमंत्री अमित शाह झूठ और अफवाह मत फैलाइये

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में साथी आप नेता राघव चड्ढा द्वारा दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए सदन की एक चयन समिति का प्रस्ताव रखने वाले प्रस्ताव में फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों को खारिज कर दिया। जिसमें बताया गया कि किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। एक प्रस्ताव बनाना और नामित सदस्य इसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। संजय सिंह ने अपने बयान में अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना है। हर बात में झूठ फैलाते हैं आप। सभी दलों के लोगों से मिलकर चयन समिति बनती है। राघव चड्ढा ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों के नाम प्रस्तावित किए हैं। अगर उनकी ओर से प्रस्तावित नाम पसंद नहीं है तो आप चयन समिति में वो नाम नहीं लीजिए। आप मसले पर विशेषाधिकार दिखा रहे हैं।

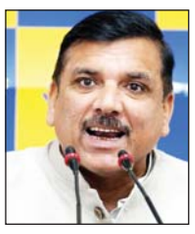

आगे आप सांसद संजय सिंह का कहना है, देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़े हैं। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता झूठे और बेबुनियाद केस के जरिए छीन ली गई, वैसे ही वे राघव की सदस्यता छीनना चाहते हैं। वे बहुत खतरनाक लोग हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम आम आदमी के सिपाही हैं। हम उनसे डरते नहीं हैं। हम उनसे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अगर राघव की सदस्यता छीनी गई तो वह निर्वाचित होकर वापस आएंगे और उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

हालांकि, सिंह ने ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि नियम कहते हैं कि कोई भी सदस्य अपने हस्ताक्षर की आवश्यकता के बिना चयन समिति में शामिल करने के लिए किसी साथी सदस्य का नाम प्रस्तावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइनों से परे सदस्यों को चयन समिति के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है और यदि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो यह उन पर निर्भर है।

चड्ढा ने विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए उच्च सदन में चयन समिति का प्रस्ताव रखा था, जिसे सोमवार को 131 से 102 वोटों के साथ पारित कर दिया गया।

केजरीवाल, संजय सिंह को मानहानि मामले में राहत देने से अदालत का इनकार

अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया था। सत्र न्यायाधीश एजे कनानी की अदालत ने मेट्रोपोलिटन अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह करने वाली आप नेताओं की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के सिलसिले में केजरीवाल और सिंह के 'व्यंगात्मक' और 'अपमानजनक' बयानों को लेकर दायर किया था।

आप नेताओं के वकील पुनित जुनेजा ने कहा कि अदालत ने शनिवार को अपना आदेश जारी किया और गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी। जुनेजा ने कहा कि केजरीवाल और सिंह ने मानहानि मामले में मेट्रोपोलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी और अपनी मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान सत्र अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी तथा उनकी मुख्य याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। मेट्रोपोलिटन अदालत ने दोनों नेताओं को इस संबंध में जारी समन को लेकर 11 अगस्त को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम पर की गई टिप्पणी बेहद अशोभनीय थी: हरीश साल्वे

नई दिल्ली। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे ने राहुल गांधी को मोदी मानहानी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा को निलंबित किये जाने पर अपनी राय रखते हुए कहा कि कोर्ट ने उन्हें मामले की योग्यता के कारण राहत नहीं दी है बल्कि सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वायनाड की जनता के प्रति चिंता प्रगट करते हुए ऐसा किया है।

समाचार चैनल से बात करते हुए हरीश साल्वे ने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम में की गई टिप्पणी बेहद अशोभनीय थी क्योंकि वो जिस तरह के सार्वजनिक जीवन में हैं, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है।

उन्होंने कहा, राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाना चाहिए या नहीं यह एक अलग मुद्दा है लेकिन उनके बात करने का तरीका बेहद अपमानजनक था। आप झूठे आरोप लगा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं सार्वजनिक जीवन में हूं। चाहे वह इससे कितना भी इनकार करें लेकिन हर कोई जानता है कि वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। क्या उनके कद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है?

साल्वे ने जोर देते हुए कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ कहा कि उन्होंने जो भी कहा था, वह गलत था और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने दोषसिद्धि पर इस कारम से रोक लगा दी क्योंकि दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला आने तक उन्हें वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने देना चाहिए। इसीलिए उनको मिली राहत योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि वायनाड की जनता को देखते हुए दिया गया है।

मालूम हो कि राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में मोदी उपनाम को लेते हुए एक विवादित भाषण दिया था। जिस पर उनके खिलाफ गुजरात के सूरत से भाजपा विधायक पुर्णेश मोदी ने सूरत के कोर्ट में मानहानि का केस किया था। जिसमें कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट की इस सजा के कारण राहुल गांधी की केरल के वायनाड से लोकसभा सांसदी चली गई थी और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राहुल गांधी की टिप्पणी बेहद अनुचित थी लेकिन सजा के कारण न केवल राहुल गांधी बल्कि वायनाड की जनता भी प्रभावित होगी। इस कारण सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी की सजा को सजा को निलंबित करने का आदेश दिया।

व्हीलचेयर पर पहुंचे मनमोहन सिंह भाजपा ने बताया बेहद शर्मनाक

नईदिल्ली। सोमवार को तीखी बहस के बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक को मंजूरी मिल गई। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी गठबंधन के लिए यह किसी परीक्षा से कम नहीं था। यही कारण था कि दोनों ओर से पूरी ताकत दिखाई गई। यही कारण था कि बीमार पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को उच्च सदन में उपस्थित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, भाजपा को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। दरअसल, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष अपनी संख्या बढ़ाने के लिए व्हीलचेयर पर बैठे पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और झामुमो के बीमार सिभु सोरेन को सदन में लाया। सत्तारूढ़ भाजपा ने ट्विटर पर व्हील-चेयर पर बैठे पूर्व पीएम की एक तस्वीर ट्वीट की। भाजपा ने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि याद रखेगा देश, कांग्रेस की ये सनक! कांग्रेस ने सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी व्हील चेयर पर बैठाये रखा वो भी सिर्फ़ अपना बेईमान गठबंधन ज़िंदा रखने के लिए! बेहद शर्मनाक! कांग्रेस ने हर वोट के लिए खूब कोशिश की लेकिन बिल को पास होने से नहीं रोक पाई। इस बीच, कांग्रेस ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद बिल को पारित होने से रोकने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राज्यसभा में वोट करने की इजाजत भी दी। पूर्व सीएम, जो अगले महीने 91 साल के हो जाएंगे, ने व्हीलचेयर पर राज्यसभा में भाग लिया।

टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन मानूसन सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित

नयी दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को मंगलवार को राज्यसभा से मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। टीएमसी नेता पर 'अशोभनीय आचरण' को लेकर यह कार्रवाई की गई। सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए ओ'ब्रायन ने नियम 267 के तहत मणिपुर हिंसा पर चर्चा शुरु किए जाने की मांग की।

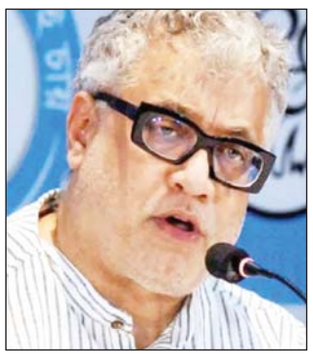

सभापति जगदीप धनखड़ ने ओ'ब्रायन द्वारा ऊंची आवाज में अपनी बात रखने पर आपत्ति जताई और उन्हें अपनी सीट पर बैठने को कहा। धनखड़ ने इसके बाद कहा कि वह ओ'ब्रायन का नाम लेते है। उन्होंने सदन के नेता गोयल से इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा।

गौरतलब है कि सभापति द्वारा जब किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो इसके साथ ही उसके निलंबन की कार्रवाई शुरु हो जाती है। गोयल ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ओ'ब्रायन लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं और आसन की अवमानना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''प्रस्ताव किया जाता है कि डेरेक ओ'ब्रायन को अशोभनीय आचरण के लिए सदन की सेवाओं से सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।' गोयल के प्रस्ताव पेश करने के बाद धनखड ने ओ'ब्रायन के निलंबन की घोषणा की। उन्होंने उन्हें सदन से बाहर जाने का भी निर्देश दिया।

इस बीच निलंबन आदेश के बाद भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। ओ ब्रायन का निलंबन धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस सांसद के बीच संसद के उच्च सदन में तीखी बहस के बाद हुआ है। सभापति ने ओ ब्रायन पर नाटकीयता में लगे रहने को एक आदत बनाने का आरोप लगाया था, जिस पर ओ ब्रायन ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिन्होंने कहा था कि वह सदन के नियमों का हवाला दे रहे थे और मणिपुर पर गंभीर चर्चा की मांग कर रहे थे।

पांच साल में दूसरी बार मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

नई दिल्ली। लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा शुरू हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। मोदी सरकार को दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 2018 में, एनडीए ने टीडीपी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था।

इस बार के अविश्वास प्रस्ताव में जिस नेता के बोलने का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है उनमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। राहुल सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार सदन में बोलेंगे। इससे पहले 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल के भाषण से ज्यादा उनके द्वारा पीएम की झप्पी की तस्वीरों ने सुर्खियां बंटोरीं थीं। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद-118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है। वहीं, नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है जिसमें सदन के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं। 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया था। अगले दिन यानी 27 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बहस की तिथि आज के लिए तय कर दी।

प्रस्ताव पारित कराने के लिए सबसे पहले विपक्षी सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव बहस के लिए तभी स्वीकार होता है जब कम से कम प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद के पास 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। यानी, अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद के प्रस्ताव पर कुल 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा कराई जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। आम तौर पर अधिक

सांसदों वाली पार्टी को बोलने का ज्यादा समय दिया जाता है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार जवाब देती है। चर्चा के बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कराते हैं या फिर कोई फैसला ले सकते हैं।

पिछली बार आए अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे की बहस हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री का डेढ़ घंटे से अधिक का संबोधन भी शामिल था। बहस के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली थी। चर्चा के दौरान अपने संबोधन के समापन पर राहुल प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और उन्हें गले लगाया था। वापसी के बाद अन्य कांग्रेस नेताओं को आंख मारकर देखा था जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।

बाद में अपने भाषण के दौरान, पीएम मोदी ने सभी दलों से इस कदम को नजरअंदाज करने का आह्वान किया और कांग्रेस पर मोदी हटाओ की मानसिकता के साथ काम करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही पीएम ने अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास मत को विपक्ष के अहंकार का परिणाम भी बताया था।

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। चूंकि, चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव है और संख्याबल की दृष्टि से सरकार को कोई खतरा नहीं है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा चुनावी होगी। इस दौरान सरकार विपक्ष पर हमले के साथ अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। वहीं, विपक्ष सरकार की खामियां गिना कर उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। विपक्ष संसद में मणिपुर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा जिसको लेकर इन दलों का दावा है कि प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं।

अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वाले गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। दोपहर 12 बजे इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। तीन दिन बहस होगी। वहीं, पीएम मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। वहीं, निशिकांत दुबे भाजपा की ओर से पहले वक्ता होंगे। भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार के पास अभी लोकसभा में 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। फिलहाल भाजपा के 300 लोकसभा सांसद हैं। इसके साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। लोकसभा में बीजद के 12 तो वाईएसआर के 22 सांसद हैं। वहीं, विपक्षी खेमे यानी इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 142 सांसद हैं। संख्याबल के हिसाब से निचले सदन में विपक्ष की तुलना में सत्ता पक्ष काफी मजबूत है।

गर्मियों में आपकी त्वचा रहेगी डिटॉक्स

धूप और गर्मी के मौसम में स्किन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है. अत्यधिक गर्मी, नमी और पर्यावरण प्रदूषकों के संपर्क में आने से आपकी त्वचा सुस्त, तैलीय और रूखी हो सकती है. इससे बचने का एक तरीका आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों और जड़ी-बूटियों को अपने आहार और स्किनकेयर रूटीन में शामिल करना है.

आयुर्वेद, भारत की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो शरीर में अच्छे स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने के लिए जोर देती है. कुछ आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ और जड़ी-बूटियां अपने औषधिय गुणों के लिए जानी जाती हैं, जो त्वचा से विषाक्त पदार्थों को साफ करने में मदद कर सकती हैं, जिससे फ्रेश और सॉफ्ट स्किन महसूस हो सके.

1. हल्दी

हल्दी एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह सूजन को कम करके, रंगत में सुधार करने में मदद करता है. आप अपने आहार में हल्दी का सेवन कर सकते हैं या निखार पाने के लिए अपनी त्वचा पर हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं.

2. नीम

नीम अपने जीवाणुरोधी और एंटी-फंगल गुणों के लिए जाना जाता है, जो इसे त्वचा को डिटॉक्सीफाई करने के लिए एक उत्कृष्ट जड़ी बूटी बनाता है. यह त्वचा को साफ करने, रोमछिद्रों को बंद करने और मुंहासे निकलने से रोकने में मदद करता है. आप अपनी त्वचा को डिटॉक्सीफाई करने के लिए अपने स्किनकेयर रूटीन में नीम के तेल या नीम के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. आंवला (भारतीय करौदा)

आंवला एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन सी का एक पावरहाउस है, जो त्वचा को डिटॉक्सीफाई करने और कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है. यह त्वचा को फिर से जीवंत करने में मदद करता है और इसे एक स्वस्थ चमक देता है. आप आंवले का रस या पाउडर के रूप में सेवन कर सकते हैं, या अधिकतम लाभ के लिए अपनी त्वचा पर आंवले का तेल लगा सकते हैं.

4. त्रिफला

त्रिफला तीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों - अमलकी, बिभीतकी और हरीतकी का एक संयोजन है. यह अपने विषहरण गुणों के लिए जाना जाता है और पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है,जो बदले में स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देता है. आप त्रिफला का सेवन पाउडर या कैप्सूल के रूप में कर सकते हैं.

[भविष्यफल]

मेष
आज आपका दिन उत्तम रहेगा व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विवेक से कार्य करें। विरोधी सक्रिय रहेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

वृष
आज आपका दिन बढ़िया रहेगा और पराक्रम बढ़ेगा। आय में वृद्धि होगी। पराक्रम बढ़ेगा। किसी बड़े काम को करने में रुझान रहेगा।

मिथुन
आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा । वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। कोई आवश्यक समाचार मिल सकता है।

कर्क
आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा । थौड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पुराना रोग उभर सकता है। भागदौड़ रहेगी। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा।

सिंह
आज आप खुशनुमा रहेंगे और आय में वृद्धि होगी। भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी। कोई बड़ा लाभ हो सकता है।

कन्या
आज आपका दिन अनुकूल रहेगा और सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेशादि शुभ रहेंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे।

तुला
आज आपका दिन अनुकूल रहेगा और सुख के साधन जुटेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेशादि शुभ रहेंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे।

वृश्चिक
पूजा-पाठ में मन लगेगा। कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा।

धनु
आज आपका दिन सामान्य रहेगा व धनार्जन होगा। लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

मकर
आज आपकी व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ रहेगा।

कुंभ
आज दूसरों से अपेक्षा पूर्ण नहीं होने से खिन्नता रहेगी। कार्य में विलंब होगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी।

मीन
आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा व अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। किसी बड़ी बाधा के दूर होने से प्रसन्नता रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा।

गर्मियों में दिखना है कूल और स्टाइलिश तो इस तरह के कपड़े पहनें

तपती गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में घर से बाहर निकलते समय ऐसे कपड़े पहनने का मन करता है जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो। लेकिन स्टाइल का क्या? क्योंकि स्टाइलिश दिखना है तो ट्रेंडी कपड़े पहनना भी जरूरी है। तो बता दें कि इस समर सीजन आप अपने मन के मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं। सिंपल और क्लासी लुक के साथ ही बोल्ड और वाइब्रेंट कलर भी खूब जमेंगे। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से फ्लोरल प्रिंट और पेस्टल कलर के साथ कुछ बोल्ड लुक भी ट्राई किया जा सकता है। आप अगर स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक की तलाश में जो ट्रेंड से मैच करें। तो इन कपड़ों को अपनी वॉर्डरोब का हिस्सा जरूर बना लें।

फ्लोरल ड्रेस और डेनिम जैकेट

अगर आप हमेशा स्टाइल में रहना पसंद करती हैं तो डेनिम की जैकेट या शर्ट तो जरूर रखी होंगी। तो बस इस गर्मी अपने फ्लोरल पैटर्न की ड्रेस के साथ डेनिम जैकेट या शर्ट को ट्राई करें। ये कूल लुक देने के साथ ही कंफर्टेबल भी बनाएगा। आप डेनिम जैकेट के साथ ट्यूब डिजाइन ड्रेस से लेकर नूडल स्ट्राईप ड्रेस तक को आसानी से पहन सकती है।

जंपसूट है ट्रेंडी

फ्लोरल प्रिंट के जंपसूट इस गर्मी के सीजन में ना केवल खूबसूरत लुक देंगे। बल्कि आप काफी स्टाइलिश भी दिखेंगी। दोस्तों के साथ मस्ती करनी हो या फिर डिनर के लिए जाना हो। फ्लोरल पैटर्न के जंपसूट को आप हाई हील्स या स्नीकर के साथ मौके के हिसाब से पेयर करें।

क्रॉप टॉप

क्रॉप टॉप का फैशन इस साल भी ट्रेंड में बना हुआ है। इसे आप हाई वेस्ट जींस, शार्ट्स, स्कर्ट, पैंट किसी के साथ भी पेयर कर सकती हैं। ये हर तरीके से स्टाइलिश लगेगा। क्रॉप टॉप के डिजाइन की काफी सारी वैराइटी रहती है। जिसे आप अपने कंफर्ट और ओकेजन के हिसाब से चुनें। दिशा पाटनी से लेकर अनन्या पांडे अक्सर अपने एब्स को फ्लांट करने के लिए लो वेस्ट जॉगर्स पैंट के साथ क्रॉप टॉप पहने दिख जाती हैं।

टैंक टॉप

टैंक टॉप गर्मियों का फेवरेट आउटफिट है। जो कूल एंड स्टाइलिश लुक देता है वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। टैंक टॉप में मलाइका अरोड़ा कई बार स्टाइलिश लुक में नजर आ चुकी हैं। जॉगर्स पैंट से लेकर टाइट फिटिंग जींस या शार्ट्स के साथ इसे आसानी से पेयर किया जा सकता है।

जॉगर्स पैंट

अगर आप गर्मियों में जींस पहनने से परहेज करती हैं तो इस बार जॉगर्स पैंट को ट्राई करें। ये काफी हल्के और स्टाइलिश दिखते हैं। इन्हें अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर कूल लुक दिया जा सकता है। तो इस गर्मी लेटेस्ट ट्रेंड के साथ रेडी हों और हर किसी की अटेंशन बटोर लें।

हर लड़की को हाई हील्स पहनना काफी पसंद होता है। इसे पहनने से ना सिर्फ लड़कियों में आत्म विश्वास आता है बल्कि वो फैशनेबल भी लगती हैं। लड़की की हाइट चाहे कितनी भी हो, पर उन्हें हील्स पहनना काफी अच्छा लगता है।

हाई हील्स पहनकर चलने में होती है दिक्कत तो अपनाएं ये तरीके, रहेंगी कंफर्टेबल

हर लड़की को हाई हील्स पहनना काफी पसंद होता है। इसे पहनने से ना सिर्फ लड़कियों में आत्म विश्वास आता है बल्कि वो फैशनेबल भी लगती हैं। लड़की की हाइट चाहे कितनी भी हो, पर उन्हें हील्स पहनना काफी अच्छा लगता है। भले ही कोई लड़की कितनी भी स्टाइलिश हो, पर उन्हें हील्स पहनने में परेशानी जरूर होती है। हील्स पहनने से पैरों में दर्द होने लगता है। वहीं अगर आप अपने शरीर के हिसाब से हील्स नहीं पहनेगीं तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। अक्सर ये देखा जाता है कि, लड़कियों को हाई हील्स पहनने की आदत नहीं होती है, क्योंकि वो रोजाना हील्स नहीं पहनतीं। ऐसे में किसी खास ओकेजन पर हाई हील्स पहनने के चलते उनके पैरों में दर्द और खिंचाव होने लगता है। जिसकी वजह से ही लड़कियां काफी असहज महसूस करने लगती हैं और हाई हील्स पहनने से कतराना शुरू कर देती हैं। इसी के चलते आज हम आपको हील्स पहनने के कुछ खास टिप्स बताएंगे, जिनको फॉलो करके आप आसानी से हील्स पहन सकती हैं।

हील्स के साइज का रखें ध्यान

हील्स खरीदते वक्त इसके साइज का ध्यान जरूर रखें। अगर ये ढीली होगी तो बार-बार पैर मुड़ने लगेगा। वहीं अगर हील्स टाइट हुईं तो आप खुद ही असहज रहेंगी।

पहले से करें प्रैक्टिस

अगर आप कार्यक्रम के पहले से ही हील्स पहनने की प्रैक्टिस करेंगी तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। अगर हील्स पहनने से आपके पैरों में दर्द होता है तो पैरों की सिकाई जरूर करें।

ब्लॉक हील्स से करें शुरूआत

अगर आपने अभी तक कभी हील्स नहीं पहनी हैं तो सबसे पहले ब्लॉक हील्स को ही ट्राई करें। ये काफी कंफर्टेबल होती हैं। कभी भी पहली बार पेंसिल हील्स ना पहनें।

पम्प्स हील्स कर सकती हैं ट्राई

अगर आप पेंसिल हील्स नहीं पहनना चाहती हैं तो पम्प्स पहनने से शुरुआत कर सकती हैं। 2-3 इंच लम्बी हील्स पहनकर ही हील्स पहनने की शुरुआत करें। जब आदत पड़ जाए तो और ज्यादा लंबी

मुहांसे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए करें ये योगासन

गर्मियों और मानसून के मौसम में कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं। इस मौसम में अधिक तापमान के कारण त्वचा संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा खान-पान में गड़बड़ी, अपच की समस्या और बिगड़ी लाइफस्टाइल के कारण भी कील, मुंहासे और पिंपल्स की शिकायत हो सकती है। पिंपल चेहरे की सुंदरता को कम कर देते हैं। वहीं गर्मी में टैनिंग और चेहरे की चमक भी उड़ जाती है। मुंहासे और दाग-धब्बे से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। घरेलू नुस्खों के अलावा कई महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बेदाग त्वचा पाने की कोशिश करते हैं, साथ ही स्किन समस्याओं से बचने के लिए कई उपाय गर्मियों में करना शुरू कर देते हैं। हालांकि योग के जरिए भी त्वचा संबंधी परेशानियों को कम किया जा सकता है। नियमित तौर पर योग करने से चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे और त्वचा की सेहत में सुधार किया जा सकता है। आइए जानते हैं स्वस्थ त्वचा के लिए योगासन।

सिंहासन

कील-मुहांसे से छुटकारा पाने के लिए सिंहासन का अभ्यास फायदेमंद है। इस आसन को करने से चेहरे के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जवां दिखने और एक्ने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सिंहासन के अभ्यास के लिए मैट पर बैठ कर दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर की जांघ पर रखें और दाएं पैर को बाईं जांघ पर रखें। अब आगे की ओर झुककर घुटनों के बल हाथों को फर्श पर टिकाएं। दोनों हाथों को सीध में रखते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे की ओर खींचें और मुंह खोलकर जीभ को बाहर निकालें। नाक से सांस लें और आंखों को खुला रखें। शेर की मुद्रा में बैठकर ये आसन 20-30 सेकेंड्स में 5-6 बार दोहराएं। अब पुरानी स्थिति में आ जाएं।

सर्वांगासन

शरीर के साथ ही त्वचा को हेल्दी रखने के लिए सर्वांगासन का अभ्यास लाभकारी है। इस आसन से पाचन और लिवर स्वस्थ रहता है। शरीर के विषाक्त पदार्थ निकलते हैं और एक्ने, एक्जिमा जैसी समस्याएं दूर होती हैं। झुर्रियों और त्वचा में बैक्टीरिया दूर करने के लिए यह योगासन फायदेमंद है। इस आसन को करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेटकर दोनों हथेलियों को नीचे रखें। पैरों को सीधे हवा में ऊपर उठाएं और सिर की ओर मोड़ें। हाथों से कमर को सहारा देते हुए कंधे, रीढ़ की हड्डी और हिप्स को सीधा रखें। इस स्थिति में 30 सेकेंड रहें और फिर धीमी गति से पुरानी स्थिति में आ जाएं।

बैलून फेस

पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए बैलून फेस योगासन कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए मुंह को बैलून के आकार में फुला लें। 10 सेकंड तक चेहरे को फुलाए रखें। इस आसन को किसी भी समय कर सकते हैं। नियमित बैलून फेस आसन को करने से पिंपल्स की समस्या दूर होती है।

इन 6 असरदार होममेड फेस पैक से ऑयली व बेजान स्किन को कहें अलविदा

बढ़ते हुए तापमान ने कहीं आपके चेहरे की चमक को तो नहीं घटा दिया ? कहीं तेज धूप, पसीने और धूल मिट्टी ने चेहरे की कोमलता, ताजगी और ग्लो तो नहीं छीन लिया? अगर ऐसा है तो यहां दिए गए आसान होममेड फेस पैक ट्राय करके देखिए हो सकता है आपकी ड्राई या ऑयली स्किन ग्लो करने लगे।

गर्मियों में घर पर बने प्राकृतिक फेस पैक त्वचा के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। घर पर नेचुरल प्रोडक्ट्स से तैयार किये गए फेस पैक गर्मियों के दौरान त्वचा को आराम दे सकते है और आमतौर पर यह सेफ होते है क्यूंकि इनमें कोई केमिकल मिक्स नहीं किया जाता। अक्सर देखा गया है की आसान होम मेड फेस पैक्स छोटी बड़ी स्किन प्रोब्लेम्स से छुटकारा दिला सकते हैं। इनमें त्वचा हाइड्रेट करना, गर्मी से स्किन की सुरक्षा करना, मुंहासों को रोकना, अतिरिक्त तेल को हटाना, त्वचा को एक्सफोलिएट करना और त्वचा को आराम देना शामिल है। इस आर्टिकल में जानिए गर्मियों के दौरान नेचुरल होम मेड फेस पैक क्यों जरूरी है और कैसे आसानी से उन्हें बनाया जा सकता है।

खीरा, एलोवेरा और टमाटर जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को धूप के हानिकारक प्रभावों से बचा सकते हैं। इसका फेस पैक बनाने के लिए 1/4 कप खीरे का रस और 1/4 कप टमाटर का रस मिलाएं। इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर लगाएं और पानी से धोने से पहले 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें।

शहद, दही और दूध से त्वचा को हाइड्रेशन मिल सकता है। खासकर गर्मियों के दौरान यह त्वचा शुष्क होने से बचा सकता है। 1/4 कप खीरे के गूदे में 2 बड़े चम्मच दही मिलाएं। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में पानी से धो लें।

नीम, हल्दी और चंदन से बना फेस पैक गर्मियों में त्वचा पर मुंहासों को रोकने में मदद कर सकता हैं। 8-10 ताजी नीम की पत्तियां, 2 चम्मच चंदन पाउडर, 1/4 कप खीरे का गूदा, 2 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच शहद लें। नीम की पत्तियों को पीस कर बारीक पेस्ट बना लें। इसे चंदन पाउडर व खीरे के गूदे के साथ अच्छी तरह मिलाएं। फिर गुलाब जल और शहद मिलाएं और तब तक हिलाएं जब तक कि यह सॉफ्ट पेस्ट न बन जाए। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक या सूखने तक लगा रहने दें। इसे ठंडे पानी से धो लें और अपने चेहरे को पैट ड्राई करें।

नींबू या संतरा और बेसन का फेसपैक चेहरे पर ज्यादा तेल को हटाने में मदद कर सकता है। गर्मियों के समय विशेष रूप से यह फायदेमंद होता है। क्योंकि इस समय त्वचा तैलीय हो जाती है। 1/2 कप बेसन में 4 स्पून नींबू या संतरे का रस मिक्स करते हुए सॉफ्ट पेस्ट बना लें। इसे अपने चेहरे पर लगाएं और पानी से धोने से पहले 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें।ओटमील या चावल का पाउडर और चीनी से बना फेस पैक त्वचा को एक्सफोलिएट करने और डेड स्किन हटाने में मदद करता है। गर्मियों के दौरान जब त्वचा बेजान हो जाती है तो यह फेस पैक यूज कर सकते हैं । 1/2 कप चावल के आटे और 4 चम्मच चीनी में आवश्यकता अनुसार दूध, दही या पानी मिलकर एक सॉफ्ट पेस्ट बना लें । इस पेस्ट को ब्रश या उंगलियों की मदद से अपने चेहरे पर लगाएं। इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पानी से अपने चेहरे से धो लें।

एलोवेरा, खीरा, और गुलाब जल त्वचा को शांत करने में मदद कर सकते हैं। जब गर्मी और पसीने के कारण त्वचा में जलन होने लगती है इस दौरान यह विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। 1/4 कप खीरे का गुदा और 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। साथ में कुछ बूंदें गुलाब जल की डालें। इसका अच्छा पेस्ट बना लें। अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पानी से धोने लें।

संक्षिप्त समाचार

शंकरलाल साहू पिछड़ा वर्ग विभाग में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बने

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव के द्वारा श्री शंकर लाल साहू पिता स्व. मेहतर लाल साहू रायपुर को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करते हुए जिला सूरजपुर, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव व कांकेर जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है.श्री साहू की नियुक्ति से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग को मजबूती मिलेगी। इनकी नियुक्ति से प्रदेश में हर्ष व्याप्त है। कांग्रेस नेताओं से स्व.साहू को याद करते हुए कहा कि वे आजीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे अब उनके बेटे की सक्रियता से पार्टी को और मजबूती मिलेगी।

अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ की हड़ताल खत्म

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मंगलवार को यहाँ उनके निवास कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को संघ की विभिन्न मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उन्हें उचित कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, संघ की प्रांताध्यक्ष श्रीमती माधुरी मृगे, प्रवक्ता श्री प्रमोद चौबे, सचिव श्रीमती गीता साहू एवँ अन्य सदस्य उपस्थित थे। पिछले वर्ष 20 अक्तूबर से चल रहा दिवंगत शिक्षाकर्मी अनुकंपा पीडित संघ का धरना स्थगित हो गया है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मृगे ने हड़ताल को स्थगित करने की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मृगे ने बताया कि हमारी मांग पर सरकार राजी हो गई है। सीएम साहब से आश्वासन मिला है, इसलिए हम सरकार को अवसर देते हुए आंदोलन स्थगित कर रहे हैं।

194 शासकीय आईटीआई में आरक्षण नियमों के अनुरूप मिलेगा प्रवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विभाग के अंतर्गत संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन राज्य में संचालित 194 शासकीय आईटीआई में सत्र 2023-24 एवं 2023-25 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन 01 जून 2023 से 11 जून 2023 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित की गई थी। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 09 अगस्त 2023 को प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी। प्रवेश हेतु संशोधित समय सारिणी विभागीय वेबसाइट cgiti.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

13 व 15 अगस्त को रद्द रहेगी चेन्नई एक्सप्रेस

बिलासपुर। दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा रेल मण्डल के विजयवाड़ा-गूडूर जंक्शन सेक्शन के बीच तीसरी रेलवे लाइन का कार्य जाएगा, इस लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए कुछ गाडियों का परिचालन प्रभावित रहेगा । यह कार्य 11 से 15 अगस्त तक किया जा रहा है । 13 अगस्त को गया से चलने वाली गाड़ी संख्या 12389 गया-चेन्नई एक्सप्रेस व 15 अगस्त को चेन्नई से चलने वाली गाड़ी संख्या 12390 चेन्नई-गया एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

17, 18, 19, 22 और 23 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का होगा आयोजन

रायपुर। जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के अध्यक्षता में डिस्ट्रीक्ट प्लेसमेंट सेल का गठन किया है। इस सेल के माध्यम से अगस्त महीने मे प्लेसमेंट कैंप और लोन मेले का आयोजन किया जाएगा। यह क्रमशः इस प्रकार है, आइटीआई सड्डू में 17 अगस्त को हॉस्पिटेलिटी (होटल एवं रेस्टोरेन्ट), शासकीय पॉलिटेक्निक बैरन बाजार में 18 अगस्त को हेल्थ केयर सेक्टर के लिए , आडवानी आर्लिकॉन स्कूल बीरगांव में 19 अगस्त को उद्योगो में तकनीकी पद, लाईवलीहुड कॉलेज जोरा में 22 अगस्त को फायनेंस, बीमा, सिक्योरिटी एवं अन्य पद गैर तकनीकी पद और लाईवलीहुड कॉलेज जोरा में 23 अगस्त को स्वरोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा।

अब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर बुलंद होगी राहुल की आवाज : भूपेश

रायपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल खुशी जताई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर राहुल गांधी की आवाज बुलंद होगी। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वैसे तो कोई आशंका नहीं थी, लेकिन जिस तरह मोदी सरकार या लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कराने और उनका बंगला खाली करने में तत्परता दिखाई थी, वैसी तत्परता नहीं दिखाई गई। राहुल गांधी ने केंद्र से सवाल क्या पूछ लिया पूरी बीजेपी सरकार ने उन्हें फंसाने के लिए ताकत झोंक दी थी।

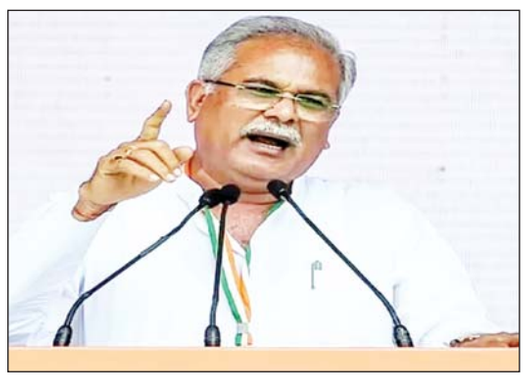

सीएम ने कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि लेकिन जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां की कांटे आगे बढ़ रही थीं, वैसे-वैसे कांग्रेसियों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब वह अध्याय खत्म हो गया है। राहुल गांधी की सदस्याता बहाल हो चुकी है। यह लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी को ढेर सारी बधाइयां। देश के सबसे बड़े मंच पर वह अपनी बात रख सकेंगे। देश की जनता उन्हें सुनना चाहती है। राहुल गांधी ने केंद्र से सवाल क्या पूछ लिया पूरी बीजेपी सरकार ने ताकत झोंक दी थी। उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए पूरे गुजरात के जितने मामले हैं, वहां से लेकर बंगला खाली कराने और सदस्यता खत्म कराने तक हथकंडे अपनाए गए।

राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी

उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी एक व्यक्ति से इतनी डरी हुई क्यों है? एक तरफ लगातार पीएम नरेंद्र मोदी वंदे मातरम भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द और विलंब से चल रही हैं। समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं, इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ जब कोई घटना होती है, तो रेल मंत्री जाते हैं। इसके विपरित उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में विरल बसाहट और रेलवे के सस्ता-सुगम साधन को देखते हुए जितने भी रेलवे की सुविधाएं हैं, वह जनता को मिलनी चाहिए। ट्रेन स्टेशन पर रुके और यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है कि ट्रेन टाइम पर चले। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को इस संबंध में खत लिखा है।

भर्ती और एडमिशन में एक ही आरक्षण व्यवस्था

वहीं भर्तियों के शुरू करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि भर्तियां तो शुरू हो चुकी थीं, लेकिन कॉलेज में जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें कुछ विसंगति आ रही थी। भर्तियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है, वही एडमिशन में भी होनी चाहिए। इसलिए कैबिननेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है।

12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने बघेल का वित्तमंत्री से अनुरोध, लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत लिखा है। पत्र में जीएसटी प्राधिकरण की ओर से पेईंग गेस्ट के रूप में रूम में और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के किराए पर 12 फीसदी जीएसटी के अतिरिक्त भार से फ्री करने का अनुरोध किया है। उन्होंने 12 फीसदी जीएसटी न लेकर राहत देने की गुजारिश की है।

मुख्यमंत्री पत्र में कहा है कि प्राधिकरण के इस निर्णय से कई गरीब मेधावी छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। उन्हें वापस घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वित्त मंत्री से अनुरोध करते हुए हुए केन्द्र सरकार के स्तर से हस्तक्षेप करने की बात कही है। वहीं हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 12 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त भार से पहले की तरह मुक्त करने और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित के लिए आग्रह किया है।।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की ओर से हाल ही में 12 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के आदेश से गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के पालकों के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार उठाने में काफी कठिनाई होगी। क्योंकि पहले से ही गरीब और निम्न वर्ग के लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। इसलिए इस संबंध में आदेश जारी किया जाए। बता दें कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और पीजी के किराए पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का आदेश दिया है।

आजादी के संघर्ष को बयां करते दास्तान-ए-आजादी कार्यक्रम सराहनीय: मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित दास्तान-ए-आजादी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन श्री दुर्गा देवी शिक्षण समिति, पार्क फाउंडेशन एवं सन्मति वेलफेयर सोसायटी द्वारा संस्कृति विभाग और छत्तीसगढ़ प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। दास्तान-ए-आजादी कार्यक्रम में श्री हिमांशु वाजपेयी, सुश्री प्रज्ञा शर्मा, श्री वेदांत भारद्वाज तथा श्री अजय टीपानिया द्वारा भारत की आजादी के इतिहास की रोचक शैली में संगीतमय प्रस्तुति दी गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि आज 8 अगस्त है और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। 8 अगस्त 1942 को आज ही के दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आन्दोलन का आगाज किया था। यह आन्दोलन पूरे विश्व में अहिंसात्मक आंदोलन का अनूठा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश को आजादी दिलाने में महापुरूषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका सपना केवल आजादी हासिल करने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे आजाद भारत के नवनिर्माण का सपना भी देख रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब वे भविष्य के भारत की रूपरेखा भी तैयार कर रहे थे। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले आधुनिक भारत का सपना देखा। आजादी मिलने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की बुनियाद रखी।

मुख्यमंत्री ने श्री बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर केन्द्रित दास्तान-ए-आजादी कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में यहां के तमाम बुद्धिजीवी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में देश की आजादी में महापुरूषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को बड़ी ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। यह सब कुछ किस्सागोई के माध्यम से दादी नानी से कहानियों के माध्यम से भी सुना करते थे। उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज दास्तान-ए-आजादी का कार्यक्रम हम लोग सुन रहे थे, यह कार्यक्रम अत्यंत शिक्षाप्रद भी है।

देश के विकास में आदिवासी समाज का भी महत्वपूर्ण रहा है योगदानः राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश के सर्व आदिवासी समाज एवं नागरिकों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि आज का दिन अपनी संस्कृति, रीति-रिवाज, भाषा, मान्यताओं और विचारों पर गौरवान्वित होने का दिन है।

राज्यपाल ने कहा कि जनजाति समाज के लोग सरल, सहज और निश्छल होते है। प्रकृति से इनका सहज नाता होता है। जिसके सानिध्य में रहते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करते है। वीरता और स्वाभिमान उनके प्राकृतिक गुण होते हैं। इतिहास गवाह है कि समय आने पर वे देश की रक्षा के लिए डटे रहे और अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। आदिवासी समाज के शहीद बिरसा मुण्डा, वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधूर, रानी दुर्गावती, जैसे असंख्य क्रांतिवीरों को मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। देश के विकास में आदिवासी समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केन्द्र शासन और राज्य शासन आदिवासियों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

विस अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की दी बधाई

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, पूरे विश्व में आदिवासी जनजाति को बढ़ावा देने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए पूरे विश्व में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता हैं। डॉ. महंत ने कहा कि, दुनिया भर में रहने वाली पूरी आबादी के मौलिक अधिकारों (जल, जंगल, भूमि) और उनके सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक संरक्षण का विपणन करने के लिए मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है।

जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस समारोह में शामिल होंगे सीएम भूपेश

- मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री पहुंचे जगदलपुर, एयरपोर्ट में हुआ आत्मीय स्वागत
- आज विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

जगदलपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने बस्तर प्रवास के लिए जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट नियमित विमान से पहुँचे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव भी पहुँचे। उद्योग मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, उपाध्यक्ष श्री विक्रम मड़ावी के द्वारा अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 अगस्त को जगदलपुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में विश्व आदिवासी दिवस समारोह में शामिल होंगे।

इस दौरान बस्तरवासियों को 637 करोड़ से ज्यादा रुपयों की सौगात सीएम देंगे। जिनमें 486 करोड़ 70 लाख के 1838 कार्यों का भूमिपूजन और 150 करोड़ 32 लाख के 462 कार्यों का लोकार्पण करेंगे।

छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बस्तर के आदिवासी हर साल 9 अगस्त को धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। हाल ही में बस्तर के आदिवासी विधायक और नेता मुख्यमंत्री निवास रायपुर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री को विश्व आदिवासी दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था। उनके न्यौता को स्वीकार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं।

इस अवसर श्री संसदीय सचिव श्री रेखचन्द जैन, चित्रकोट विधायक श्री राजमन बेंजाम, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, नगर निगम सभापति श्रीमती कविता साहू, अक्षय ऊर्जा अभिकरण के अध्यक्ष श्री मिथलेश स्वर्णकार, इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजीव शर्मा, सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इसके साथ प्रशासनिक अधिकारियों में कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, आईजी श्री सुंदरराज पी., कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र मीणा,कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के संचालक श्री धम्मशील गणवीर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित ने भी स्वागत किया।

कौशिक के बयान पर सीएम भूपेश का तंज

दुर्ग/भिलाई। सीएम भूपेश बघेल ने धरमलाल कौशिक और तत्कालीन रमन सरकार पर 15 साल तक धोखा देने का आरोप लगाया है। सीएम ने बिजली की दर बढ़ने को लेकर केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही केंद्र सरकार पर बिजली बनाने के लिए उपयोग होने वाला कोयला महंगा करने का आरोप भी लगाया।मुख्यमंत्री भूपेश ने धरमलाल पर कसा तंज- सीएम भूपेश ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ में धोखे के अलावा कुछ नहीं किया। 15 साल तक भाजपा ने हर वर्ग को, आदिवासियों को, महिलाओं को छला। अब जब यहां की जनता सुखी है तो बयानबाजी कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार भरोसे का सम्मेलन करवा रही है, क्योंकि लोगों को सरकार पर भरोसा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा धोखा देने वाले तो धोखे की बात ही ना करें। किसानों को उन्होंने कहा था कि 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। 15 साल उनको मौका मिला, कभी 2100 रुपये दिये? 300 रुपये बोनस हर साल उन्होंने देने की बात कही थी। मिला क्या ? उनके कार्यकाल में युवाओं को कभी बेरोजगारी भत्ता मिला? मिला भी तो थोड़ा बहुत।

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भूपेश सरकार के भरोसे के सम्मेलन को लेकर हमला बोला था। उन्होंने कांग्रेस सरकार के इस सम्मेलन को धोखे का सम्मेलन बताया था। कौशिक ने भूपेश सरकार पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया था।

छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल भरोसे का सम्मेलन कर अपने सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 2023 से हुई थी। जिसमें शामिल होने प्रियंकगा गांधी बस्तर आई थी। बस्तर संभाग के जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी ने विशाल जनसभा का आयोजन किया था। जिसके बाद से ही सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के कई जगहों में भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के दौरान किसानों ने लिया ज्यादा कर्ज, कर्जमाफी की उम्मीद

रायपुर। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। जिसके बाद भूपेश बघेल की सरकार ने 16 लाख 65 हजार किसानों का कर्ज माफ किया। 6100 रुपए की कर्जमाफी के बाद भूपेश सरकार ने लगातार किसानों के हित में कई काम और योजनाएं लाईं। इस साल सरकार ने किसानों को 6100 करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य रखा है। जिसमें 30 जुलाई 2023 की स्थिति में अब तक 13 लाख 16 हजार 184 किसानों को 5785 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। जो लक्ष्य का लगभग 95 फीसदी है। वहीं पिछले 4 साल के आंकड़ों की बात करें तो इस साल कर्ज देने का आंकड़ा काफी ज्यादा है।

बीजेपी का सरकार पर हमला

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि वो किसानों के हित में काम कर रही है।लेकिन विरोधी ऐसा नहीं मान रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के शासन में प्रदेश में अमानक बीज और खाद, नकली कीटनाशक का बाजार बढ़ा है। जिसके कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्जे का नया इतिहास बन गया है। किसानों को अपनी आजीविका चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है।

बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, लगातार किसानों का कर्ज बढ़ा है। 2018 -19 में 3287 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को लेना पड़ा। 2019-20 में 3981 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा। 2020-2021 में 4495 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा,वहीं 2021-2022 में 4747 करोड़ का कर्ज लिया गया। 2023 - 2024 की बात की जाए तो जुलाई 2023 तक 5785 करोड़ का कर्ज लिया गया है। जोड़ा जाए तो 14000 हजार करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज लिया गया है।

बीजेपी की मानें तो 15 साल की रमन सरकार थी।उसके बाद कांग्रेस ने 12 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया। मतलब ये है कि 15 साल में किसानों ने 12 हजार कर्ज लिया।वहीं वर्तमान में 4 साल में 14 हजार से भी ज्यादा का कर्ज लिया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार कहती है कि किसानों की स्थिति बेहतर है लेकिन किसान इतना कर्ज क्यों ले रहे हैं इसका जवाब भूपेश सरकार को देना चाहिए।

बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार

बीजेपी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर के मुताबिक प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद, कृषि फायदे धंधा बन चुका है। प्रदेश के किसान कर्ज मुक्त हुए हैं। प्रदेश के किसानों को धान की कीमत 2640 से 2660 रुपए मिली है। देश के किसी भी राज्य के किसानों को धान की कीमत इतनी नही मिल रही है। रमन सिंह सरकार के दौरान 18 लाख हेक्टेयर में धान की पैदावार होती थी।वह आज बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर से ऊपर हो गया है। रमन सरकार में 12 से 15 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीयन कराते थे। आज प्रदेश के 29 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है।

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा जब कृषि कार्य लाभकारी हुआ तो किसानों की संख्या में भी वृद्धि हुई, रकबा बढ़ा है। उपज की सही कीमत मिल रही है। कृषि कार्य के समय किसानों को खाद और बीज के लिए सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से लोन मिल रहा है,इसलिए कर्ज का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो हर किसान कृषि कार्य के समय सरकारी बैंकों से खाद बीज और कृषि कार्य के लिए ऋण लेते हैं। धान कटाई के बाद जब किसान धान सोसाइटी में बेचते हैं और वह राशि मिलने के बाद किसान उन्हें लौटा देते हैं। हमारी सरकार में बेहतर रिकॉर्ड बना है।

कांग्रेस के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी ही नहीं है।इसलिए वे अज्ञानता से इस प्रकार की बात करते हैं। आज देश के किसानों की हालत खराब है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। अमानक खाद दिया जाता है। समय पर खाद नहीं मिलता, इससे मध्य प्रदेश, गुजरात ,हरियाणा जैसे भाजपा शासित राज्यों की हालत खराब है। छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है, किसान बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो बैंकों से किसान जो सहायता लेते है वह बढ़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस ने किसानों के कर्ज लेने के कारण को अलग-अलग तरह से बताया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसान कर्ज माफी की उम्मीद से कर्ज नहीं ले रहे।भले ही सीएम भूपेश बघेल ने किसानों का कर्ज सीएम बनने के तीन घंटे के अंदर माफ किया हो। बावजूद इसके किसानों के लिए कई सारे काम किए। जिससे किसानों के अंदर सरकार के प्रति भरोसा पैदा हुआ।

वहीं भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ का इस बारे में अलग मत है। यूनियन के प्रवक्ता गिरधर पटेल की माने तो पूर्ववर्ती सरकार मात्र 10 क्विंटल धान खरीदती थी।छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब 15 क्विंटल धान खरीदी की गई। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदी करने की घोषणा की है। इसलिए किसान ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए कृषि सहायता के लिए कर्ज ले रहे।

चुनावी साल में किसानों को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार उनके हित में कई घोषणाएं कर सकती है। इसलिए इस किसानों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए कर्ज लिया है। भले ही बीजेपी कांग्रेस पर ये आरोप लगा रही है कि पिछले 15 साल की बीजेपी सरकार और कांग्रेस की मौजूदा सरकार के दौरान लिए गए कर्ज में अंतर है। लेकिन ये भी बात माननी होगी कि किसानों की खेती का रकबा और पैदावार दोनों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ किसानी के काम में परंपरागत किसान भी वापस लौटे हैं।

कांग्रेस राज में आदिवासियों को न्याय नहीं: नेताम

नाबालिग आदिवासी बच्ची के रेप के आरोपी का भागना कांग्रेस सरकार पर कलंक

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने कहा है कि सरगुजा संभाग के रामानुजगंज में एक पहाड़ी कोरवा नाबालिग किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म, साथी युवक के साथ हुई लूट की घटना और गिरफ्तार आरोपियों के फरार होने के बाद प्रदेश सरकार का नाकारापन एक बार फिर जाहिर हुआ है। श्री नेताम ने कहा, यह शर्मनाक वारदात बताती है कि आदिवासियों के प्रति प्रदेश की कांग्रेस सरकार कतई संवेदनशील नहीं है।

भाजपा के पूर्व सांसद श्री नेताम ने कहा कि जब से कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता सम्भाली है, आदिवासियों पर अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश में चहुँओर कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, मासूम बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं की अस्मिता के लुटेरे दरिंदगी की हदें पार करते जा रहे हैं और प्रदेश सरकार सियासी ड्रामेबाजी में मशगूल है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद भी प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था के राज की दुहाई देती है तो यह प्रदेश को शर्मसार करने वाली बात है। श्री नेताम ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया भी संवेदनहीनता का परिचायक है। दुष्कर्म के मामलों की

एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की कोताही कई सवाल खड़ा कर रही है। यह स्पष्ट होना चाहिये कि तत्काल घटना की शिकायत दर्ज कराने पहुँची पीड़िता को पहले दिन बैरंग क्यों लौटाया? क्या आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देकर बचाने की कोशिश की जा रही है?

भाजपा के पूर्व सांसद श्री नेताम ने कहा कि इस वारदात के गिरफ्तार आरोपियों के पुलिस हिरासत से भाग जाने से भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन के स्तर पर आरोपियों का कोई सीधा कनेक्शन है? आरोपियों को भाग जाने का अवसर देकर सत्तावादी राजनीतिक दबाव को अंजाम दिया गया है? शासन-प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि आरोपियों को कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है और पुलिस पर कौन राजनीतिक दबाव बना रहा है? श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी कन्या छात्रावास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची, मंदिर जाने वाली मासूम किशोरियाँ तक अगर हैवानों की दरिंदगी की शिकार हो रही हैं तो प्रदेश की इस कांग्रेस सरकार के राज पर लानत है। अगर बच्चियों की सुरक्षा यह सरकार और उसके कारिंदे सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी बेशर्म और नाकारा सरकार को छत्तीसगढ़ पर असहनीय बोझ बनकर एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

भाजपा के पूर्व सांसद श्री नेताम ने कहा कि इस घटना से प्रदेश की कांग्रेस सरकार का घोर आदिवासी विरोधी चरित्र एक बार फिर बेनकाब हुआ है। संवेदनशीलता का बेसुरा राग अलापते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी संवेदनहीन पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर मौन क्यों साधे बैठे हैं? श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा में जिन आँकड़ों का हवाला दिया है, उससे इस बात की तस्दीक हो रही है कि कांग्रेस के पूरे शासनकाल में लगभग 5 हजार वारदातें दुष्कर्म की घटी हैं। इनमें आदिवासी समुदाय की बच्चियों, किशोरियों, युवतियों व महिलाओं के साथ घटी वारदातों का आँकड़ा छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाला है। महिला सुरक्षा के तमाम सरकारी दावे खोखले साबित हुए हैं। श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश सरकार के निकम्मेपन की सजा प्रदेश की निर्दोष बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाएँ भुगत रही हैं और कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि दुष्कर्म के आरोपियों को संरक्षण देकर प्रदेश को गर्त में धकेल रहे हैं।

कांग्रेस बताएं शिक्षा तबादला घोटाले का सरगना कौन है? : ओपी चौधरी

रायपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कह कि घोटाले पर घोटाला करने वाली कांग्रेस सरकार का एक और बड़ा घोटाला जनता के सामने आ चुका है। यह मामला बेहद संवेदनशील इसीलिए भी है क्योंकि यह प्रदेश की पूरी शिक्षा प्रणाली को दूषित कर रहा है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को मुख्यमंत्री जी ठीक तो नहीं कर सके, लेकिन शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेन-देन का खेल जरूर कर दिया। इसे शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे जी ने भी स्वीकारा है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की जड़े इतनी गहरी जमा दी है कि उसका प्रभाव अब छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। प्रदेश में सेटिंग एवं एटीएम की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मिस्टर एटीएम बनकर भ्रष्टाचार के इन पैसों को गांधी परिवार को पहुंचा रहे है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पहले सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की पदोन्नति की व्यवस्था थी जिसमें 15000 पदों के लिए पदोन्नति की गई जो सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर बने। पदोन्नति होने के बाद पद स्थापना के लिए काउंसलिंग का आयोजन ही नहीं किया। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब सभी पद काउंसलिंग के आधार पर दिया जाता था एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत किया जाता रहा लेकिन दुर्भाग्य की बात रही 15000 पदों में प्रमोशन देने के बाद पद स्थापना के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं किया। सहायक शिक्षक से शिक्षक एवं शिक्षक से मिडिल स्कूल के शिक्षकों के 12000 पदों के लिए काउंसलिंग तो की गई लेकिन पद स्थापना भारी मात्रा में पैसा लेकर किया गया। शिक्षा व्यवस्था को समाज का दीपक माना जाता है जिसमें भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है

मुख्यमंत्री जी जवाब दें

पहला सवाल - आखिर माननीय हाईकोर्ट को शिक्षकों का तबादला आदेश निरस्त क्यों करना पड़ा?

दूसरा सवाल - 15 हजार शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल हेड मास्टर में प्रमोशन के बाद पदस्थापना में काउंसलिंग क्यों नहीं की गई?

तीसरा सवाल - 12 हजार शिक्षकों के प्रमोशन के बाद पदस्थापना में भारी पैसा लेकर संशोधन क्यों किया गया?

चौथा सवाल - आखिर इस भ्रष्टाचार के पीछे के मूल सरगना कांग्रेसियों पर कार्यवाही कब की जायेगी?

पांचवा सवाल - अधिकारियों पर कार्यवाही करके मोहरों को कब तक प्रताड़ित करेंगे? मुख्यमंत्री जी असली चेहरों को सामने लाने के लिए क्या न्यायिक जांच आयोग के गठन का साहस कब जुटा पायेंगे?

इस दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी मौजूद रहे।

मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर का किया निरीक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा हाईकोर्ट के मामलों की सुनवाई पश्चात् औचक निरीक्षण हेतु महासमुंद पहुंचे। उनके द्वारा न्यायालय परिसर के समस्त कक्षों, पार्किंग, उद्यान, अधिवक्ताओं व पक्षकारों हेतु बैठक व्यवस्था इत्यादि का निरीक्षण किया गया। न्यायालय की अधोसंरचना पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया गया। निरीक्षण में उद्यान का रख-रखाव उचित नहीं पाये जाने पर चिंता जाहिर की तथा सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने महासमुंद जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कुल 13,997 प्रकरण लंबित है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने लंबित जमानत आवेदनों की भी जानकारी ली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद ने जानकारी दी कि जमानत आवेदन पत्रों पर त्वरित सुनवाई की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा पुराने प्रकरणों को भी प्राथमिकता के साथ निराकृत करने हेतु निर्देश दिए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के कुल 1200 प्रकरण लंबित है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम व ऐसे प्रकरण, जिनमें राजीनामा हो सकता है, के भी त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रकरणों में अनावश्यक स्थगन न दिए जाए।

मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं से भी चर्चा की व उनकी समस्याएं सुनी। औचक निरीक्षण में उनके साथ रजिस्ट्रार जनरल श्री अरविन्द कुमार वर्मा तथा एडिशनल रजिस्ट्रार कम पीपीएस श्री एम.वी.एल.एन. सुब्रहमन्यम भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने जी-20 समन्वय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की

रायपुर। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में भारत की जी-20 अध्यक्षता पर समन्वय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जरूरी और लॉजिस्टिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस संबंध में शेरपा (जी-20) सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) और सचिव (सूचना एवं प्रसारण) ने प्रस्तुतिकरण दिए। भारतीय अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, जिनमें हरित विकास, सतत विकास लक्ष्यों को तेज करना, मजबूत सतत संतुलन और समावेशी वृद्धि, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, लैंगिग समानता और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों को गतिशील बनाना शामिल था।

शेरपा (जी-20) ने सूचित किया कि कुल 185 बैठकें आयोजित की गई है, जिनमें 13 बैठकें मंत्रिस्तरीय थीं। देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इसके दायरे में रखा गया था। कुल 12 परिणाम दस्तावेजों के अलावा सहमति के साथ 12 योग्य प्रस्तावों को अपना लिया गया है।

- **नई दिल्ली में 9 और 10 सितम्बर को आयोजित होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए जरूरी और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की**
- **शिखर सम्मेलन के लिए 3200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मीडियाकर्मियों ने पंजीकरण करवाया**

सचिव (डीईए) ने बताया कि वित्त मामलों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें क्रिप्टो संपदा एजेंडा, वित्तीय समावेश, जलवायु वित्त को कार्यशील बनाना तथा सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त पोषण शामिल हैं। सचिव (सूचना एवं प्रसारण) ने मीडिया के लिए किए जाने वाले बंदोबस्त के बारे में जानकारी दी, जैसे मीडिया सेंटर और मीडिया प्रत्ययन की व्यवस्था। अब तक शिखर सम्मेलन के लिए 3200 से अधिक मीडियाकर्मियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें 1800 विदेशी और 1200 से अधिक भारतीय मीडियाकर्मी हैं। उन्होंने सूचित किया कि विदेशी और भारतीय मीडिया, दोनों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

प्रमुख सचिव ने लॉजिस्टिक और सुरक्षा पक्षों से जुड़े पिछले निर्णयों को लागू करने के विषयों की भी समीक्षा की। दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त (दिल्ली पुलिस) सहित सुरक्षा अधिकारियों ने सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आने वाले गणमान्यों की अगवानी, यातायात प्रबंधन योजना, हवाई अड्डे और सुरक्षा इंतजाम तथा दिल्ली एनसीआर में सौन्दर्यीकरण के कामकाज के बारे में बताया। अगले महीने जी-20 राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी के संबंध में अब तक की जाने वाली सकारात्मक प्रगति को मद्देनजर रखते हुए प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित व्यक्तियों व विभागों को अगले कुछ दिनों के भीतर समस्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया, ताकि रिहर्सल शुरू की जा सके। मिश्रा ने समस्त शासकीय तंत्र की भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि समय पर समुचित तैयारियां सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन को एक महीना रह गया है, इसलिए सारे कामों को पूरी सटीकता के साथ पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि विस्तार से सारी रूपरेखा तैयार की जाए और कामकाज को सही ढंग से पूरा करने के लिए अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देशभर के युवा अधिकारियों को शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तथा संगठन से सीखने का अवसर मिल रहा है।दिल्ली के उपराज्यपाल, कैबिनेट सचिव और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दबाया गया: बैज

रायपुर। विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनायें देते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदिवासियों की

संस्कृति सभ्यता, सवंर्धित करने का काम हुआ, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का बहाल किया गया। उनके शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिये न सिर्फ योजनायें बनाई गई उन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि पूर्व के रमन सरकार के दौरान सबसे ज्यादा पीड़ित, प्रताड़ित और शोषित आदिवासी वर्ग था। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके कानूनी अधिकारों का हनन किया गया। आदिवासी वर्ग के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार से काम नहीं किया गया था। भाजपा ने 2003 में आदिवासियों को 10 लीटर दूध वाली गाय देने का वायदा किया था, हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी का वायदा किया था, पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के दौरान बस्तर के 600 गांव उजाड़े, तीन लाख से अधिक आदिवासियों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। 1379 फर्जी प्रकरण दर्ज कर हजारों आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद किया गया था जिसे जस्टिस पटनायक कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर रिहा किया गया।

कृषि विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तकनीकी कर्मचारी संघ (टी.एस.ए.) के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आज यहां स्वामी विवेकानंद सभागार, कृषि महाविद्यालय, रायपुर में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि रायपुर ग्रामीण विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा ने केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय इकाईयों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवायी। इस अवसर पर तकनीकी कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी सदस्यों को भी शपथ दिलवायी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल सदस्य श्री आनंद मिश्रा एवं श्रीमती वल्लरी चन्द्राकर भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि सत्यनारायण शर्मा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निवर्हन करने का आव्हान किया। उन्होंने कर्मचारी संघ की सभी उचित मांगों को वे राज्य शासन तक पहुंचाकर उनका समाधान करवाने का आश्वासन दिया। समारोह को कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल एवं प्रबंध मण्डल सदस्य श्री आनंद मिश्रा ने भी संबोधित किया। शपथ ग्रहण समारोह में केन्द्रीय तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. पी.के. सांगोडे ने स्वागत भाषण दिया तथा महासचिव डॉ. जी.डी. साहू ने संघ की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय इकाई रायपुर के अध्यक्ष डॉ. गजेन्द्र चन्द्राकर ने तकनीकी कर्मचारियों की समस्याएं बताई तथा अतिथियों से इनका शीघ्र निराकरण किये जाने की मांग की।

गौशाला के नाम से 1677 करोड़ का घोटाला : ठाकुर

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के द्वारा 15 अगस्त को सड़क पर गाय घूमते दिखने पर कलेक्टर कार्यालय में ले जाकर बांधने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को 15 अगस्त की तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि आज से और अभी से नारायण चंदेल को कहीं भी इक्का-दुक्का गाय घूमते हुए नजर आती है तो उन्हें तत्काल करीब के डे केयर सेंटर गोठनों में लेकर जाना चाहिये और गौ माता की सेवा करना चाहिय। मुख्यमंत्री बघेल की सरकार ने रमन सरकार के दौरान हुई 17 हजार से अधिक गायों की हत्या के पाप से भाजपाइयों को मुक्ति दिलाने प्रदेश में 10,000 से अधिक गोठनों का निर्माण किये हैं। नारायण चंदेल के सामने रमन सरकार के दौरान भाजपा नेताओं की गौशाला में निर्दयता से बेरहमी से गायों की हत्या हुई थी उसका प्रायश्चित करने का अच्छा अवसर है।नारायण चंदेल और भाजपा नेताओं की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है जो भाजपा गौ सेवा के नाम से आम जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर वोट लेती थी वह 15 साल में छत्तीसगढ़ में गौशाला के नाम से 1677 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। गौमाता के चारागाह की जमीन पर भाजपा नेताओं ने कब्जा कर लिया।

अनियमित और भ्रष्टाचार को कोई संरक्षण नहीं : सुरेंद्र वर्मा

रायपुर। भ्रष्टाचार और अनियमित को लेकर भूपेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यवाहियों पर भाजपा नेताओं के अनर्गल बयानबाजी को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि 15 साल सुपर सीएम के अधीन सरकारी विभागों को

ठेके पर चलाने वाले भाजपाई किस नैतिकता से भूपेश सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता पूर्ण प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं? भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों से किए गए वायदे के अनुरूप पदोन्नति और पदस्थापना के लिए पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था लागू की है। पदोन्नति क्रमोन्नति और पदस्थापना के लिए कर्मचारी संगठनों से समन्वय स्थापित कर प्राप्त सुझावों के अनुरूप पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। पदोन्नति के पश्चात संशोधन को लेकर जरूर शिकायतें आई ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया और व्यवस्था में हेरफेर कर अनियमितताएं बरती गई ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर न केवल बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई है बल्कि जांच के उपरांत एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। भूपेश सरकार में किसी भी तरह की अनियमित और भ्रष्टाचार को कोई संरक्षण नहीं है। भूपेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाइयों से भाजपाइयों में इतनी छटपटाहट क्यों? भ्रष्ट अधिकारियों से साठ-गांठ है, मिलीभगत है या सहभागी हैं? या भाजपाई ही असल षड़यंत्रकारी हैं? रमन सिंह के कुशासन में हर विभाग के लिए काउंटर तय होते थे एक सुपर सीएम हुआ करते थे जिनके निर्देशन और संरक्षण में सभी विभाग ठेके पर दिए गए थे।

देवगुड़ियों के विकास से अवैध कटाई पर हुआ नियंत्रण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा राज्य के सुदूर वनांचल में वनवासियों के आस्था का केन्द्र ''देवगुड़ियों'' का संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से जारी है। इस तारतम्य में जगदलपुर वनवृत के अंतर्गत बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर वनमंडल के वन क्षेत्रों में ग्रामीणों की आस्था के प्रतीक देववन, देवगुड़ी तथा देव सरना आदि का संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इनमें वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक 94 देवगुड़ियों में संरक्षण एवं संवर्धन कार्य अंतर्गत उनके बाउण्ड्रीवॉल तथा चैनलिंक फैंसिंग इत्यादि का कार्य शत-प्रतिशत् पूर्ण कर लिया गया है।इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने जानकारी दी कि इनके विकास कार्य के लिए कैम्पा के तहत 4 करोड़ 58 लाख रूपए की राशि स्वीकृत थी। मोहम्मद शाहिद ने बताया कि देवगुड़ियों के संरक्षण एवं संवर्धन से स्थानीय वनवासियों के विश्वास तथा आस्था को मजबूती मिली है। जिससे स्थानीय वनवासी आज वन विभाग को अवैध कटाई, अतिक्रमण पर रोकथाम सहित अग्नि सुरक्षा आदि के कार्यों में वनों के विकास के लिए परस्पर सहयोग प्रदान करने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि जगदलपुर वनवृत जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है।यहां पर निवासरत जनजातियों में विभिन्न प्रकार की स्थानीय मान्यताओं के साथ-साथ कई देवी-देवताओं का पूजन किया जाता है।

पारिस्थितिक तंत्र, स्वास्थ्य एवं कल्याण" विषय पर हुई कार्यशाला

रायपुर। 31 वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2023 के तहत पारिस्थितिक तंत्र, स्वास्थ्य एवं कल्याण विषय पर 33 जिला समन्वयकों एवं शिक्षकों की एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आज रीजनल साईंस सेन्टर रायपुर में किया गया। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जिला एवं राज्य पर प्रतिवर्ष किया जाता है। राज्य स्तर पर चयनित बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेकर अपने

मॉडल प्रदर्शित करते हैं। यह कार्यक्रम 10 से 17 वर्ष के बच्चों को एक अवसर प्रदान करता है, जहां वे अपने वैज्ञानिक संकल्पनाओं को मुख्य विषय एवं उपविषयों पर शोध परियोजनाओं मॉडल आदि के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम बच्चों को प्रयोग, आंकड़ा संकलन, शोध, विश्लेषण एवं नवाचार प्रक्रिया से परिणाम तक पहुंचकर स्थानीय समस्याओं का समाधान तलाशने का अवसर प्रदान करता है। इसी कड़ी में आयोजित इस कार्यशाला में प्रबुद्धजनों ने पारिस्थितिक तंत्र के क्षय से होने वाले दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए इसे बचाने के लिए जागरूकता फैलाने पर जोर दिया।

उन्होंने कार्यशाला में जिला समन्वयकों एवं शिक्षकों से कहा कि बच्चों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित कर पारस्परिक समन्वय से बहुविषयक परियोजना बनाने हेतु प्रेरित करें। छ.ग. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा रीजनल साईंस सेन्टर, रायपुर के महानिदेशक श्री एस.एस. बजाज ने विभिन्न जिलों से आये जिला समन्वयकों एवं शिक्षकों से आग्रह किया कि पारिस्थितिक तंत्र, स्वास्थ्य और कल्याण मुख्य कथानक एवं उनके उप-विषयों से संबंधित अपने स्थानीय समस्याओं को चिन्हित कर उसके निराकरण हेतु नवाचारी परियोजनाओं के निर्माण हेतु बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करें, जो भविष्य में समाज के लिये उपयोगी हों। कार्यशाला के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के सचिव, डॉ. आर.के. सिंह ने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव और भौतिक वातावरण सम्मिलित होते हैं यह एक् जटिल तंत्र है आज के औद्योगिक युग में इसे समझना एवं इसके सुधार के लिए काम करना अत्यंत आवश्यक है।

डेयरी का धंधा करने वाला शराब कोचिया निकला

- **35 पौव्वा के साथ थाना अमला के हत्थे चढ़ा**

रायपुर। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम बड़गांव निवासी डेयरी का धंधा करने वाला 33 वर्षीय प्रेमू यादव शराब कोचिया निकला। बीते कल सोमवार को मंदिर हसौद थाना अमला ने उसे 35 पौव्वा शराब ले जाते रास्ते में धर दबोचा। शराब की मात्रा 5 लिटर से अधिक होने की वजह से उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के गैरजमानतीय अपराध के लिये जुर्म कायम कर गिरफ्तारी पश्चात न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

ज्ञातव्य हो कि ग्राम बड़गांव में अवैध शराब बिक्री की शिकायत काफी

अरसे से है । बेखौफ कोचिये ग्रामीणों को चुनौती देते हुये खुलेआम शराब बेचते हैं। शाम ढले तो बड़गांव से टेकारी व? गोढी सड़क मार्ग में राहगीरों का चलना दूभर हो जाता है। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार इस ग्राम में प्रमुख रूप से 3 कोचिये सक्रिय हैं जिसमें से तो 2 पूर्व में पकड़े जा चुके थे । इन्हीं सूत्रों के अनुसार पूर्व में पकड़े जा चुके 2 कोचियो में से एक ने तो फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान को देखते हुये अपना धंधा समेट लिया है पर दूसरा कोचिया सहित अब तक पकड़ में न आ पाये प्रेमू यादव बेखौफ धंधा चला रहा था। शाम ढले इस ग्राम में बड़गांव सहित आसपास के ग्राम टेकारी , कुंडा , तोड़गाव व मुनगेसर के पियक्कड़? जुटते थे। इसकी शिकायत लगातार पुलिस प्रशासन को मिल रही थी व वे इसे पकड़ने ताक में बैठे थे । इधर इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों ने इसकी जानकारी क्षेत्र में शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा को दी । श्री शर्मा ने बीते कल थाना प्रभारी रोहित मालेकर सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल का ध्यान बड़गांव सहित इसके नजदीकी ग्राम कुटेसर में बिक रहे शराब व? इसकी वजह से ग्रामों में व्याप्त अशांति की ओर दिलाया ।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.